छत्तीसगढ़ विधान सभा

की अशोधित कार्यवाही



(अधिकृत विवरण)



षष्ठम् विधान सभा

द्वितीय सत्र

शुक्रवार, दिनांक 09 फरवरी, 2024 (माघ 20, शक सम्वत् 1945)

[अंक 05]

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 09 फरवरी, 2024 (माघ 20, शक संवत् 1945) विधान सभा पूर्वाहन 11.00 बजे समवेत हुई. {अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष जी, आज नेता प्रतिपक्ष आ गये हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- आज इस सदन को पता लगा कि छत्तीसगढ़ विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- आप सबका धन्यवाद करता हूं। श्री अजय चंद्राकर :- हफ्ते भर तक नेता प्रतिपक्ष विहिन विधान सभा चला। डॉ. चरण दास महंत :- कल ही बस तो गायब हुआ था।

बस्तर संभाग में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अशासकीय संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई राशि [स्कूल शिक्षा]

1. (*क्र. 768) श्री किरण देव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :(क) बस्तर संभाग अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किन-किन अशासकीय संस्थाओं को जनवरी,
2021 से 15 जनवरी, 2024 तक कितनी-कितनी राशि, किन-किन कार्यो हेतु उपलब्ध करायी गयी है?
वर्षवार/संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार कितनी राशि, किन कार्यों में व्यय
की गई और कितनी शेष है ? कितनी राशि उपलब्ध कराया जाना कब से शेष है व क्यों, संस्थावार,
वर्षवार जानकारी देवें? (ग) कंडिका 'क' अनुसार किन-किन संस्थाओं के सम्बंध में शिकायतें दी गई और
उस पर जाँच की गई? निष्कर्ष क्या थे तथा दोषी पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : **(क)**, **(ख)** एवं **(ग)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे** प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।

श्री किरण देव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री से यह प्रश्न और जानकारी पूछना चाहता हूं कि बस्तर संभाग के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किन-किन अशासकीय संस्थाओं को जनवरी 2021 से 2024 आज पर्यन्त तक कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु उपलब्ध कराई गयी है। इस राशि को संस्थावार किस मद में और किस योजना के अंतर्गत किस कार्य योजना में कितनी राशि खर्च की गयी, मैंने वर्षवार के हिसाब से जानकारी मांगी है। इसमें जानकारी जरूर लिखित में आई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय :- उनका प्रश्न पूरा नहीं हुआ है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि बस्तर में अशासकीय शालाओं की संख्या प्राथमिक 106 है, पूर्व माध्यमिक 237 है, हाई स्कूल 57 है, हायर सेकेण्डरी 67 है। इस प्रकार 467 प्राईवेट विद्यालय हैं और उन प्राईवेट विद्यालयों को कुल एक करोड़ 45 लाख 8,255 रूपए विभिन्न मदों में दिए गए हैं और उतना ही खर्च हो गया है।

श्री किरण देव :- माननीय मंत्री महोदय, यह जो जानकारी विभाग की तरफ से बनकर आई है, मैंने वर्ष 2021, 2022 और 2023 का पूछा है। स्वाभाविक रूप से 2021, 2022 और 2023 में जितनी भी जानकारी आएगी निरंक ही आनी है। सारी जानकारियों में सिर्फ भुगतान की गई राशि की जानकारी है। किस कार्य हेतु किस उपयोग में खर्च किया गया है, इसको सिम्मिलत किया गया है। कहीं गणवेश के लिए, कहीं विभिन्न कार्य योजना के लिए खर्च की गयी है। अब इस राशि का उपयोग न ही भौतिक सत्यापन की दृष्ट से किया गया है, क्योंकि 195 स्कूल बस्तर संभाग से जुड़े हुए हैं, ऐसी अशासकीय संस्थाओं का इसमें उल्लेख है। मंत्री महोदय जी ने 106 की संख्या दी है। ये जो स्कूलों में शासन के द्वारा अनुदान की राशि अशासकीय संस्थाओं को दी जाती है, क्योंकि अभी तक सारी जानकारियां निरंक ही है, इसका मतलब इसमें किसी प्रकार की विस्तृत कार्य योजना नहीं है, चाहे वह भौतिक सत्यापन का हो, चाहे उसके विश्लेषण का हो। इस कार्ययोजना में जांच का विषय हो, कहीं से कोई शिकायत हो, सभी मामलों में निरंक है। क्या आने वाले वर्ष में जब अशासकीय संस्थाओं को जो अनुदान शासन द्वारा दी जाएगी, उसका पूरा भौतिक सत्यापन और समग्र जांच करने का वचन देते हैं ? क्योंकि जिस कार्ययोजना के लिए जिस कार्य के लिए अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को राशि दी जाती है, इसमें किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगर कहीं किसी प्रकार की राशि की गड़बड़ी होती है तो उस विषय में इसको जांच कर उसके लिए जो भी दोषी है, उस पर कार्रवाई करेंगे क्या ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर में वर्ष 2021, वर्ष 2022 और 15 जनवरी 2023 तक शासन द्वारा अनुदान प्राप्त 43 अशासकीय शालाएं हैं। वर्ष 2021-2022 में 259 लाख रूपये का आबंटन किया गया और 259.17 लाख रूपये की राशि खर्च की गई। वर्ष 2022-2023 में

818 लाख रूपये की राशि का आबंटन किया गया और 508 लाख रूपये की राशि खर्च की गई। वर्ष 2023-2024 में 361 लाख रूपये की राशि का आबंटन किया गया और वह पूरी राशि खर्च कर दी गई। इसमें गणवेश, आकस्मिक व्यय, डाक-तार भवन मरम्मत, भवन निर्माण, फर्नीचर मरम्मत, खेल-कूद सामग्री, कम्प्यूटर, बिस्तर सामग्री, कार्यालयीन व्यय इत्यादि के लिए राशि खर्च की गई है। अभी तक हमारे पास इसकी काई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि माननीय सदस्य किरण देव जी किसी प्रकार की कोई शिकायत उपलब्ध करवाते हैं तो निश्चित रूप से हम उसकी जांच करवा लेंगे।

श्री किरण देव :- मंत्री जी, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धरमलाल कौशिक जी।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बिना निविदा सीधे सामग्री क्रय

[स्कूल शिक्षा]

2. (*क्र. 388) श्री धरमलाल कौशिक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सही है कि छ.ग. भण्डार क्रय नियम में एन.सी.सी.एफ., नेकॉफ, केन्द्रीय भंडार व स्व-सहायता समूह (हैण्डलूम व हैण्डी काफ्ट सामग्री छोड़कर) बिना निविदा से सीधे सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में कोई छूट नहीं दी गई है? यदि हां तो जनवरी, 2022 से नवम्बर, 2023 तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्यान्ह भोजन व अन्य कार्य हेतु किन-किन संस्थाओं से बिना निविदा के कितनी-कितनी राशि की कौन-कौन सी सामग्री क्रय की गई है? इसमें कितनी राशि का भुगतान किया गया है व कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? वर्षवार, जिलेवार, सामग्रीवार, संस्थावार व राशिवार जानकारी देवें? (ख) क्या प्रश्नांश "क" अनुसार खरीदी हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से छूट ली गई थी? यदि हाँ, तो छूट कब प्राप्त की गई व छूट के पश्चात् व पूर्व कंडिका "क" अनुसार संस्थाओं से बिना निविदा के क्रय की गई है? भण्डार क्रय नियम का पालन न करने पर क्या कार्यवाही की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जी हाँ। जनवरी 2022 से नवम्बर, 2023 तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्यान्ह भोजन व अन्य कार्य हेतु बिना निविदा के कोई सामग्री क्रय नहीं की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश "क" अन्सार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक का प्रश्न पूछा था, लेकिन इसमें वर्ष 2022 से वर्ष 2023 तक का उत्तर आया है इसलिए या तो हम इसको त्रुटि समझ ले। मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे इस प्रश्न को आगामी समय के लिए बढ़ा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय धरम जी, आपने जिस अविध का जिक्र किया है कि उत्तर में कटौती की गई है तो उस अविध का उत्तर पूर्व में आ चुका है इसलिए उसको संशोधित उत्तर के रूप में दिया गया है। आपको जिस अविध तक का उत्तर दिया गया है उसके पहले का उत्तर पुराने प्रश्न में आ चुका है। यदि आप इसमें प्रश्न पूछेंगे तो उचित रहेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका प्रश्न पूर्व के सालों से उद्भूत नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि वह पूर्व के सालों का भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, मैं उनको जवाब दे दुंगा।

अध्यक्ष महोदय :- हां, बिल्क्ल पूछ सकते हैं। कौशिक जी, आप प्रश्न पूछिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो खरीदी की गई है, उसमें भण्डार क्रय नियम का पालन नहीं हुआ है। बिना टेण्डर के नेकॉफ (एन.सी.सी.एफ.) और बाकी जगह से खरीदी गई है और मैं समझता हूं कि लगभग 50 करोड़ रूपये की खरीदी की गई है। मंत्री जी, जिसमें खरीदी की छूट नहीं दी गई है और उसकी खरीदी की गई है और नियम का उल्लंघन किया गया है तो क्या आप उसकी जांच कराएंगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा कि माननीय धरमलाल कौशिक जी पूर्व में इसका प्रश्न पूछ चुके हैं इसलिए आगे की date डाली गई है। वास्तव में 50 करोड़ रूपये की खरीदी नहीं की गई है, बल्कि 36 करोड़, 51 लाख, 87 हजार, 918 रूपये की खरीदी की गई है और वह 5 जिलों में खरीदी की गई है। आपका यह कहना भी सही है कि उसके लिए उनको उद्योग विभाग से छूट लेनी थी, लेकिन उन्होंने छूट नहीं ली। यह एक बड़ी खरीदी है परंतु कलेक्टर की अनुमित से खरीदी की गई। चूंकि वह कोरोना काल था और कोरोनाकाल में इन्होंने इमरजेंसी में खरीदी की है। इतनी बड़ी खरीदी करने के लिए जिस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए, जिनकी अनुमित लेनी चाहिए, वह अनुमित नहीं ली गई है। 5 जिलों सूरजपुर, मुंगेली, बस्तर, बीजापुर और कोंडागांव में लगभग 36 करोड़ रूपये की खरीदी की गई। यह माना गया है कि उन्होंने बिना अनुमित के खरीदी की है इसलिए वह दोषी हैं। उनमें से एक जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेण्ड किया गया है, दो जिला शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है और दो जिला शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ जांच संस्थित करने की कार्रवाई चल रही है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको 50 करोड़ रूपये की खरीदी की जानकारी दी तो आपने उसमें से 36 करोड़ रूपये की खरीदी को स्वीकार किया। उसमें इतनी अनियमितता हुई है कि सारे नियमों को ताक पर रखकर जिस प्रकार से बिना टेण्डर के खरीदी की गई। कोरोनाकाल आपदा में अवसर ढूंढने का एक बहाना है। भ्रष्टाचार कैसे किया जा सके तो आपदा में अवसर ढूंढना, यह कोरोना कॉल की बात कहकर बच नहीं सकते । इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि थोड़ी बहुत राशि की बात होती तो अलग है, यह बहुत बड़ी राशि है।

अध्यक्ष महोदय :- आप मंत्री जी से क्या चाहते हैं ?

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि कमेटी बनाकर उसकी जांच करें ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, क्या आप जांच करने को तैयार हैं ?

श्री धरम लाल कौशिक :- जांच करने के बाद सारी बात आगे आ जाएगी । यह एक जिला का नहीं, बह्त से जिलों का मामला है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य का बार-बार आग्रह है, जांच करा लेंगे क्या?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच हुई है । जांच में पाया गया है कि नियमों का पालन नहीं किया गया है । पूर्व में एक जिले के शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड किया गया है । माननीय कौशिक जी वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, भूपेश सरकार जो पिछली बार थी, उनके कार्यकाल का एकाध काम बता सकते हैं, जो नियमों के तहत हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय :- यदि आप क्छ नये तथ्य दे रहे हैं तो उसकी ओर ध्यान देंगे ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कोई नियमों के तहत नहीं है । वहां तो लाओ, लाओ के लिए काम होता था ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उसमें खामियां रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आपके पास कुछ नये तथ्य हैं ?

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं, कुछ नये तथ्य देने की जरूरत नहीं है । जब मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं तो गलती हुई है । यदि गलती हुई है तो उसमें अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई ? मैं कार्रवाई की बात कर रहा हूं । मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उसमें गलत हुआ है तो आप समय सीमा बता दें कि आप कब तक कार्रवाई करेंगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कौशिक जी वरिष्ठ सदस्य हैं, अनुभवी सदस्य हैं । वे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो बचे हुए चार जिलों के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनको मैं निलंबित करने की घोषणा करता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, वे संतुष्ट हो गए ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- मंत्री जी, कौन-कौन से अधिकारी हैं, अगर आपको पता है तो उनका नाम ही बता दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, कार्रवाई कर दी है।

डॉ. चरण दास महंत :- बचे हुए जिले के अधिकारी हैं, जिनको आप सस्पेंड कर रहे हैं । वह कौन-कौन से जिले हैं और कौन-कौन से अधिकारी हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरजपुर जिला में 11,36,34,730 रूपए की खरीदी की गई । मुंगेली जिला, जहां से माननीय सदस्य आते हैं, वहां पर 99,95,151 रूपए की खरीदी की गई । बस्तर जिला में 20,47,48,480 रूपए की खरीदी की गई । बीजापुर जिला में 53,64,759 रूपए की खरीदी की गई और कोण्डागांव जिले में 3,14,44,798 रूपए की खरीदी की गई ।

डॉ. चरण दास महंत :- मैंने नाम पूछा है । उनका कुछ नाम तो होगा ? जो भी महामना हैं ।

श्री धरम लाल कौशिक :- उस समय तो तत्कालीन रहे हैं, उनको सस्पेंड किया गया है ।

डॉ. चरण दास महंत :- पता तो लगे न । आप पिछले कार्यकाल के किसी को हवा में सस्पेंड कर रहे हों । आप नाम बताईए कि किसको सस्पेंड कर रहे हैं ? मैं कोई आपित नहीं कर रहा हूं, मगर आपका कोई भी प्रश्न आये तो उसकी जांच दल की घोषणा करो, कोई भी प्रश्न आये तो विधायक की जांच कमेटी बनाओ, कोई भी प्रश्न आये तो सस्पेंड करो । आप किसको सस्पेंड कर रहे हैं, नाम तो बता दीजिए ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार राय, मुंगेली के जिला शिक्षा अधिकारी श्री पी.एस. एल्मा । (हंसी)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- कलेक्टर को सस्पेंड कर रहे हैं । वे कलेक्टर हैं ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- कलेक्टर को सस्पेंड कर रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, एल्मा कलेक्टर थे।

श्री बुजमोहन अग्रवाल :- एल्मा शिक्षा अधिकारी भी नहीं हो सकता क्या ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- ये है असत्य का पुलिंदा ।

श्री कवासी लखमा :- वे कलेक्टर थे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एल्मा नहीं, लखमा बोल दूं क्या ?

श्री कवासी लखमा :- किसी को भी सस्पेंड कर रहे हैं, नाम तो बताओ । नाम बताने में क्या दिक्कत है ? किसको, किसको सस्पेंड किया है, उसका नाम बताओ ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं उसको लखमा बोल दूं क्या ?

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय मंत्री जी, आप जिसका नाम तक नहीं खोज पा रहे हो, उसको आपने कैसे खोज लिया कि करोड़ों रूपए का घपला किया है । कोई आदमी तो होगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं आपको नाम बता रहा हूं ।

डॉ. चरण दास महंत :- एक नाम बताने में दिक्कत है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने दो नाम बता दिये, तीसरा नाम भी बता रहा हूं।

डॉ. चरण दास महंत :- चिलये, बताईये। चिलये बताईये, कोई महंत है, कोई बघेल है, कौन है, बताओ तो सही ?

श्री राजेश मृणत :- आप चाहते क्या हैं किसका नाम लें ?

डॉ. चरण दास महंत :- हम जानना चाहते हैं कि कोई हमारा नाम वाला है क्या ? कोई हमारे नाम वाला है जो बदमाशी कर रहा हो ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद ठाकुर, जिला शिक्षा अधिकारी राजेश मिश्रा।

डॉ. चरण दास महंत :- ठीक है। हम संतुष्ट हो गये, धन्यवाद। मैं सोच रहा था कहीं महंत तो नहीं निकल रहा है। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं-नहीं, उस समय जिला शिक्षा अधिकारी ये नहीं हुआ करते थे। उस समय जिला शिक्षा अधिकारी उधर बैठे हुए मंत्रिमण्डल के सदस्य होते थे।

श्री धरम लाल कौशिक :- इन्हीं के सरंक्षण में हुआ है। हां, इन्हीं के सरंक्षण में हुआ है।

श्री कवासी लखमा :- वरिष्ठ मंत्री होकर विधानसभा में इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप लोगों को जनता ने सस्पेण्ड किया, अधिकारी को यहां मंत्री सस्पेण्ड कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी, मैं आपको पेपर कटिंग दिखा दूंगा। पेपर में लिखा है कि [xx]¹

श्री कवासी लखमा :- वह आपका कटिंग है।

श्री अजय चन्द्राकर :- [xx]

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, अजय जी, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। विधानसभा में किसी भी माननीय मंत्री के लिए इस प्रकार की बात मजाक में भी करना उचित नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं। यदि आप अनुमित दें तो मैं पेपर की किटोग पटल पर रख देता हूं। मैंने पेपर किटोग का उल्लेख किया। मैं आरोप लगाऊंगा तो लिखकर लगाऊंगा। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अजय चन्द्राकर जी ने हंसी-मजाक में जिस बात को कहा है, आप उसको विलोपित कर दीजिये। परन्तु माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी चूंकि इस मामले की जांच चल रही है, मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। वास्तव में पांचों जिलों में और सूरजपुर जिले के शिक्षामंत्री कौन से जिले से थे, आप यह जरा बता दें ?

अध्यक्ष महोदय :- विलोपित।

-

¹ [xx] अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार विलोपित।

डॉ. चरण दास महंत :- भईया, मैं तो यह कह रहा हूं कि आप जिसको सस्पेण्ड करना है किरये। हमने किसी के लिए मना नहीं किया है। हम अधिकारी के पक्ष में नहीं हैं। जिसने भी गलत काम किया हो, चाहे वह शिक्षा विभाग का हो, चाहे आबकारी विभाग का हो, चाहे लोक निर्माण विभाग का हो, चाहे मुख्यमंत्री के विभाग का हो, जिसको सस्पेण्ड करना हो, किरये। मगर आपको सरकार चलाने के लिए जनादेश मिला है, 5 साल के गड्ढे खोदने के लिए नहीं मिला है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, हम गड्ढे नहीं खोद रहे हैं। प्रश्न आ रहा है तो हम जवाब दे रहे हैं।

डॉ. चरण दास महंत :- आप सुनिये न, हमारे पास भी है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम आपकी भी आंख खोल रहे हैं कि आप लोगों ने बच्चों के निवाले पर डाका डालने का काम किया है। 36 करोड़ रूपये, छोटा-मोटा काम नहीं है।

डॉ. चरण दास महंत :- मैं आपको किसी बात के लिए कहां रोक रहा हूं।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना भर्राशाही हुआ है। भर्राशाही हुआ है, यह तो लगेगा ही। बचाने का प्रयास किये और बचाये।

श्री धर्मजीत सिंह :- इनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करा दीजिये।

डॉ. चरण दास महंत :- कौशिक जी, 15 साल तक आपकी सरकार रही, उसमें भी क्या-क्या, कहां-कहां गड्ढे हुए, कितना भर्राशाही हुआ, उसी पर आ जाते हैं। आप 5 साल की चर्चा करो हम 15 साल की चर्चा करते हैं। अगर विधानसभा इसीलिए बना है तो ..।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर आपति है।

डॉ. चरण दास महंत :- किस बात की आपित है ?

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं यह बोल रहा हूं कि जिस बात को नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं कि हम 15 की चर्चा कर लेते हैं। आप मुझे यह बताईये कि यह प्रश्नकाल है। हम प्रश्नकाल के लिए प्रश्न लगायेंगे। अभी हम कौन से विषय में प्रश्न लगायेंगे, वही प्रश्न लगेगा जो ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता जी पिछली सरकार के भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं।

डॉ. चरण दास महंत :- गलत बात, बिलक्ल गलत बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बिलक्ल समर्थन कर रहे हैं।

ंडॉ. चरण दास महंत :- चन्द्रांकर जी, बिलकुल गलत बात बोल रहे हैं। आपने 15 साल में क्या-क्या किया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप जो 15 साल की बात कर रहे हैं....। दो तीन साल का लगायेंगे, आने वाले समय में हमारी सरकार भी चार साल की हो जायेगी तो भी उनके खिलाफ में लगेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- सदन के प्रश्न पर उत्तर दिया ।

अध्यक्ष महोदय :- धरम जी, कृपया बैठ जायें ।

श्री धरमलाल कौशिक :- लेकिन, आपित है मुझे । माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 साल का लगाओं करके बोल रहे हैं तो हम प्रश्न वही लगायेंगे, जो अनियमितता हुई है, जो सरकार रही है, उसी अनियमितता को हम लोग लगायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल ठीक है, बैठ जाईये । कृपा करके इसे समाप्त करे।

डॉ.चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ । मगर आपको यह कह रहा हूँ कि यह सरकार 15 साल बनाम 5 साल के लिये नहीं बनी है । आपको सरकार चलाना है, विकास करिये ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं बनी है, चिलये । विकास कार्य के लिये बनी है, बैठ जाईये । बिल्कुल ठीक, धन्यवाद । श्री आशाराम नेताम ।

कांकेर जिले में नरहरदेव आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में डी. एम. एफ. मद से किया गया खर्च [स्कूल शिक्षा]

3. (*क्र. 591) श्री आशा राम नेताम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- कांकेर जिले में नरहरदेव आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में जनवरी, 2019 लेकर दिसम्बर, 2023 तक डी.एम.एफ. मद एवं विभागीय मद से क्या- क्या कार्य कराये गये हैं ? सभी कार्यों में कार्यवार कितनी राशि खर्च की गई है ? प्रश्नांकित अविध में क्या कराये गये कार्यों के बीच में तकनीकी स्वीकृति ली गई है? अगर हां, तो किस आधार पर कार्य के बीच में तकनीकि स्वीकृति ली गई है? तकनीकी स्वीकृति लेने के पहले ठेकेदार को कितना भुगतान कर दिया गया था ? वर्तमान में क्या कोई कार्य लंबित है या नहीं? अगर हां, तो क्या कारण हैं ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : कांकेर जिले में नरहरदेव आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में जनवरी 2019 लेकर दिसम्बर 2023 तक डी.एम.एफ. मद एवं विभागीय मद से कराये गये कार्य एवं कार्यवार खर्च राशि की जानकारी संलग्न प्रपत्र² अनुसार है। प्रश्नांकित अविध में कराये गये कार्यों के बीच में तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जी नहीं, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री आशा राम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, स्कूल शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि कांकेर जिला के नरहरदेव आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में जनवरी 2019 से लेकर दिसम्बर 2023 तक डीएमफ मद और विभागीय मद से क्या-क्या कार्य कराये गये हैं ?

_

² परिशिष्ट "एक"

अध्यक्ष महोदय :- बैठ जाईये, फिर दूसरा प्रश्न करिये । आप तीन प्रश्न कर सकते हैं । पहला हुआ, दो और करिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जो कांकेर में नरहरदेव उत्कृष्ट विद्यालय है, उसमें डी.एम.एफ.विभागीय मद और समग्र मद के वर्षवार जो है, यह लगभग 6 करोड़ 96 लाख 19 हजार 122 रूपये की स्वीकृति दी गई । इसमें से 5 करोड़ 36 लाख 98 हजार 660 रूपये, खर्च किया गया है । यह जो खर्च किया गया है, वह कक्ष के जीर्णोद्धार, टायलेट बनाने में, प्रयोगशाला बनाने में, पुसतकालय बनाने में, खेल मैदान बनाने में एवं अन्य कार्यों में इस प्रकार से खर्च किया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की चिन्ता जायज है कि एक-एक स्कूलों में इतनी अधिक धन राशि जीर्णोद्धार में खर्च की गई, इतने पैसे में नई स्कूल की बिल्डिंग बन सकती थी । (शेम-शेम की आवाज) यह सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक है । हमने कल भी इस बात को कहा था कि जीर्णोद्धार में आपने इतना पैसा खर्च दिया ? में नहीं चाहता कि हम पुरानी चीजों को खोदें, हर चीज की जांच करायें । अब जो पूर्व के प्रश्न में कलेक्टरों की अनुमित से हुआ । (शेम-शेम की आवाज) माननीय नेता जी, जो वास्तविक स्थिति है, उसमें एक स्कूल के जीर्णोद्धार में 5 करोड़ रूपये खर्च कर दिये । यह औचित्यपूर्ण है ?

डॉ.चरणदास महंत :- अभी मैं आ रहा था तो आपने जवाब दिया कि यह सब कलेक्टरों की अनुमति से ह्आ है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हां-हां ।

डॉ.चरणदास महंत :- कलेक्टर के ऊपर कार्यवाही करो ना ? क्यों नहीं करते हो ? कलेक्टर पर करो, आई.ए.एस. पर करो, आई.पी.एस. पर करो, आप बच्चे लोगों को मार रहे हो ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कलेक्टरों को आदेश कौन देता है ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, केन्द्र ने आदेश दिया था कि प्रभारी मंत्री लोगों को हटाकर कलेक्टरों को अध्यक्ष बनाना है । आपके केन्द्र के आदेश के कारण कलेक्टरों ने काम किया ।

डॉ.रमन सिंह :- भई प्रश्न आशा राम जी का है । आप उनको जवाब दीजिए, इधर जवाब देने की जरूरत नहीं है । कृपया आप बैठिये । आपके संदर्भ का प्रश्न ही नहीं है । चलिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यजनक है, डी.एम.एफ. के पैसे का और समग्र शिक्षा के पैसे का 5-5 करोड़ से अधिक राशि एक-एक स्कूलों में खर्च कर दिये गये । बच्चों के अपग्रेडेशन के लिये, उनकी पढ़ाई के लिये, उनकी व्यवस्था के लिये, जिन पैसों को खर्च किया जाना था, वह केवल निर्माण कार्यों में खर्च कर दिया गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिये माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, जो जानकारी मांगी है, क्योंकि अधिकारी जानकारी भी देने के लिये तैयार नहीं है कि कितना पैसा खर्च हुआ है ? अब सरकार बदलने के बाद में जानकारी आ रही है कि इतना-इतना पैसा इतने स्कूलों में खर्च कर दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय :- इस पूरे विषय पर क्या कोई श्वेत पत्र जारी कर सकते हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपका निर्देश है, मैं इस निर्देश के आधार पर कि जो स्वामी आत्मानंद स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय बनायी गयी हैं, उन विद्यालयों में जो खर्च किया गया है, इसकी पूरी जांच करवाकर हम अगले सत्र तक विधान सभा के पटल पर श्वेत पत्र जारी करके रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद । गजेन्द्र जी, बहुत अच्छा जवाब आ गया, उसके बाद कुछ बचता नहीं है ।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक निवेदन है कि....।

अध्यक्ष महोदय :- आपके जिले का तो नहीं है ?

श्री गजेन्द्र यादव :- जिले का नहीं है, लेकिन आत्मानंद स्कूल के भर्ती का है, माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि।

अध्यक्ष महोदय :- अलग से पूछ लीजिए । यह संदर्भ नहीं है । सुशांत शुक्ला जी ।

बिलासपुर में राज्य कैंसर संस्थान के निर्माण की अद्यतन स्थिति [चिकित्सा शिक्षा]

4. (*क्र. 627) श्री सुशांत शुक्ला: क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या राज्य केंसर संस्थान की स्थापना बिलासपुर जिले में की जा रही है? यदि हां, तो इस हेतु कहां पर, कितनी भूमि आरक्षित/अधिग्रहीत की गई है ? संस्थान कब एवं किस योजना के तहत स्वीकृत किया गया? योजना की कुल लागत कितनी है ? कितनी-कितनी राशि, निर्माण कार्य, उपकरण खरीदी तथा अन्य में व्यय किया जाना है ? निर्माण हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की जा चुकी है ? (ख) प्रश्नांश 'क' के प्रस्तावित निर्माण में केंन्द्रांश एवं राज्यांश कितना-कितना है? कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? निर्माण कार्य किस एजेंसी को दिया गया है? कार्य की अद्यतन स्थित से अवगत करावें ? (ग) केंसर संस्थान कब तक प्रारंभ किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जी हां। इस हेतु बिलासपुर जिले के कोनी (पटवारी हल्का सरकंडा) में 1.849 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है। संस्थान वर्ष 2018 में केन्द्र प्रवर्तित योजना -Strengthening of Tertiary care for Cancer Scheme of National Programme for Prevention and control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke (NPCDCS) तहत् स्वीकृत किया गया है। योजना की कुल लागत रू. 115.20 करोड़ है। जिसमें उपकरण क्रय हेतु रू.80.70 करोड़, भवन निर्माण कार्य हेतु रू.34.50 करोड़ व्यय किया जाना है। भवन निर्माण कार्य हेतु राज्य शासन से कुल रू.34.19 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। निर्माण

एजेंसी सीजीएमएससी द्वारा निविदा पूर्ण कर भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में भूतल के छत स्तर पर कार्य प्रगतिरत है।(ख) प्रश्नांक "क" के प्रस्तावित निर्माण में केन्द्रांश व राज्यांश (60.40) क्रमशः रूपये 69.12 करोड़ व रूपये 46.08 करोड़ है। वितीय वर्ष 2022-23 में निर्माण एजेंसी को रू. 20.91 करोड़ का भुगतान किया गया है। निर्माण कार्य सी.जी.एम.एस.सी. लिमि. रायपुर को दिया गया है। निर्माण कार्य लगभग 30% पूर्ण हो गया है।(ग) समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में एक सदस्य के रूप में मेरा पहला प्रश्न है और विषय बहुत गंभीर है कि केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 में केंसर संस्थानों की स्थापना की व्यवस्था दी थी, यह उससे जुड़ा प्रश्न है । प्रश्न यह है कि कृपया स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य केंसर संस्थान की स्थापना बिलासपुर जिले में की जा रही है ? यदि हां तो इस हेतु कहां पर कितनी भूमि आरक्षित /अधिग्रहित की गई है? संस्थान कब और किस योजना के तहत स्वीकृत किया गया है ? योजना की कुल लागत कितनी है ? कितनी-कितनी राशि निर्माण कार्य और उपकरण खरीदी तथा अन्य में व्यय किया जाना है ? निर्माण हेतु अब तक क्या-क्या कार्रवाई की जा चुकी है ? प्रश्नांश 'ख' के तहत 'क' के प्रस्तावित निर्माण में केंद्रांश और राज्यांश कितना-कितना है ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य, आप पहली बार चुनकर आये हैं मगर प्रश्न बहुत लंबा कर रहे हैं। आप एक प्रश्न करके बैठ जाईये, फिर दूसरा करिये फिर बैठ जाईये, फिर तीसरा प्रश्न करिये, उसको सुनिये, उसका जवाब आने दीजिये। उसके बाद फिर दूसरा और तीसरा प्रश्न करिये। यदि जरूरत होगी तो मैं चौथा प्रश्न करने का भी अवसर दूंगा।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, जी।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मंत्री के रूप में मेरा भी पहला प्रश्न है और मैं उसका जवाब दे रहा हूं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- आज दोनों का पहला अवसर है। क्या बात है। बढ़िया जवाब दीजिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिलासपुर में स्वास्थ्य की दिशा में जो राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना हो रही है, उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा है। बिलासपुर जिला के कोनी पटवारी हल्का सरकंडा में 1.849 एकड़ भूमि आरक्षित की गयी है। इस संस्थान के लिये वर्ष 2018 में केंद्र प्रवर्तित योजना - Strengthening of Tertiary care for Cancer Scheme of National Programme for Prevention and control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke (NPCDCS) के तहत स्वीकृत किया गया है। योजना की कुल लागत 115.20 करोड़ रूपये है। जिसमें उपकरण क्रय हेतु 80.70 करोड़ रूपये, भवन निर्माण कार्य हेतु 34.50 करोड़ रूपये व्यय किया जाना है। भवन निर्माण कार्य हेतु राज्य शासन से कुल 34.19 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

निर्माण एजेंसी सी.जी.एम.एस.सी. द्वारा निविदा पूर्ण कर भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में भूतल के छत स्तर पर कार्य प्रगतिरत है।

अध्यक्ष महोदय, क्या दूसरे प्रश्न का भी जवाब दे दूं ?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, बस हो गया। शुक्ला जी, आप दूसरा प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न यह है कि प्रस्तावित निर्माण में केंद्रांश एवं राज्यांश कितना-कितना है ? कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? निर्माण कार्य किस एजेंसी को दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप केंद्रांश और राज्यांश बता दीजिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित निर्माण कार्य में केंद्रांश 60 प्रतिशत व राज्यांश 40 प्रतिशत है। इसके लिये केंद्र से 69.12 करोड़ रूपये व राज्य से 46.08 करोड़ रूपये स्वीकृत है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्माण एजेंसी को 20.91 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। निर्माण कार्य सी.जी.एम.एस.सी. लिमिटेड रायपुर को दिया गया है। निर्माण कार्य लगभग 30 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, तीसरा प्रश्न करिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, कैंसर संस्थान बहुत गंभीर विषय है। यह कब तक प्रारंभ किया जावेगा ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो कार्य की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है परंतु फिर भी यदि माननीय सदस्य की जिज्ञासा है तो मैं बताना चाहता हूं कि इसमें टेण्डर के अनुसार कार्य पूर्णत: दिनांक 05.01.2025 तक की है और कोशिश यह रहेगी कि यह कार्य समय-सीमा में पूर्ण हो जाये और जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ को एक नया कैंसर संस्थान प्राप्त हो सके।

अध्यक्ष महोदय :- चिलये और कोई प्रश्न है ?

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। चूंकि मेरा प्रश्न आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की तरफ है कि पूर्ववर्ती व्यवस्था में प्रशासनिक कारणों से संबंधित निविदा दूषित हो गयी थी। उसकी व्यवस्था को सुधारते हुए आने वाले समय में सुनिश्चितता के आधार पर नियम के तहत जो समय-सीमा तय हुई है, क्या उसमें यह कैंसर संस्थान पूर्णत: को प्राप्त करेगा ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से भविष्य में जो भी इसमें जरूरत होगी, उसको पूर्ण करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर जिला में कैंसर का अस्पताल बनना है और इसके लिये हम सब चिंतित भी है कि यह बनना भी चाहिए। माननीय मंत्री जी, आपने उपकरण क्रय हेतु 80.70 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। इस संबंध में मुझे यह जानना है कि क्या भवन बनने के पहले यह उपकरण खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो गयी है ? क्योंकि इसकी बहुत लम्बी प्रक्रिया होती है। दूसरा, आप अपने दौरे में सब मेडिकल कॉलेज वगैरह जा रहे हैं, आपका प्रयास बहुत अच्छा है। मैं भी आपके संग सिम्स गया था। जहां पर यह कैंसर संस्थान बन रहा है । वहां के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर, बिलासपुर में इसकी समीक्षा करके, इसमें काम को गति प्रदान करने का कष्ट करेंगे क्या? आप यह बतायेंगे कि यह जो 80 करोड़ रूपये मंजूर हुआ है उसमें जो कैंसर के दवाई के Instrument वगैरह लगते हैं तो आपने यह instrument खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है क्या ? और आपने यह नहीं किया है तो यह कब तक होगा, यह बता दीजिए?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी चिन्ता व्यक्त की है। मुझे जब भी अगले प्रवास में बिलासपुर जाना होगा तो समय से पहले उस क्षेत्र के माननीय विधायकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे कि हम किस प्रकार से जल्द से जल्द कैंसर संस्थान प्रारंभ कर सकते हैं। हम उसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही इन्होंने सामग्री क्रय हेतु विषय रखा है, उसमें सी.जी.एम.एस.सी. द्वारा 5 उपकरणों को क्रय करने के संबंध में निविदा की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उपकरण का नाम भी बता दूंगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। अगर आप उपकरण का नाम बतायेंगे तो मेरे पिताजी भी नहीं समझेंगे।

माननीय मंत्री जी, मैं आपसे केवल यह कह रहा हूँ कि आप उच्च स्तरीय बैठक कर, संबंधित सभी अधिकारियों से उपकरण की खरीदी के लिए प्रयास तेज करिये क्योंकि ...।

अध्यक्ष महोदय :- आप इसमें बैठक करके, सुनिश्चित करिये कि समय पर सामग्री क्रय हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, यह प्रक्रिया जटिल है। आप वहां एक बार जाकर, समीक्षा तो कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी तैयार हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो रूटिन वर्क है।

अध्यक्ष महोदय :- वह आपको भी बुला लेंगे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता ही हूँ कि यह कार्य हो।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हो पाया था, उससे पहले माननीय सदस्य जी ने टोक दिया था।

अध्यक्ष महोदय :- आपका और कोई प्रश्न है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उपकरण खरीदी का ऑर्डर जो बाकी है, वह कब तक हो जाएगा ? आप हम लोगों को इसके बारे में भी जानकारी बताएं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने प्रक्रिया पूरी कर दी है। चूंकि यह उपकरण खरीदने में समय लगता है। विदेश से भी इसके कुछ उपकरण आते हैं। यह बड़ा संस्थान है। हमने प्रक्रिया चालू कर दी है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, मेरे प्रश्न पूछने का आशय ही यही है कि आपने इसके लिए राशि की घोषणा कर दी है, राशि है तो इसकी प्रक्रिया में समय लगेगा। विदेश से कुछ उपकरण आएंगे तो आप जानते हैं कि वहां बहुत धीरे-धीरे काम चलता है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक तरफ बिल्डिंग बने तो दूसरी तरफ मशीनों की खरीदी का भी काम करें। अगर आप समीक्षा करेंगे तो आपके जाने से विभाग में गित मिलेगी और यह काम आगे बढ़ेगा। यही इस प्रश्न के माध्यम से यही आपसे आग्रह है कि बिलासप्र को केवल कैंसर संस्थान चाहिए और आप उसे यह देने के लिए प्रयास करिये।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। माननीय सदस्य का सुझाव है।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बताना चाहेंगे कि क्या इसी स्थापना के साथ मनेन्द्रगढ़ में स्वीकृत कैंसर रिसर्च सेन्टर को पुनः स्वीकृत कर प्रारंभ करेंगे ? और इसे कब तक स्वीकृत करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- इसमें मनेन्द्रगढ़ कहां से आ गया ?

श्री स्शांत श्क्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ संलग्न है।

अध्यक्ष महोदय :- यह है तो ठीक है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहले स्वीकृत हुआ था।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप जवाब दीजिए।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय सुशान्त शुक्ला जी के प्रश्न पर निवेदन कर देता हूँ। पहले मनेन्द्रगढ़ में कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेन्टर के लिए स्वीकृत हुआ था। वह काम नहीं हुआ है। आप उसको भी जरा बढ़ा दीजिए। हमें उसकी भी चिन्ता है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 में केन्द्र सरकार से राज्य कैंसर संस्थान हेतु एक बिलासपुर में और मनेन्द्रगढ़ में टर्सरी केन्द्र हेतु प्रस्तावित था, परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 5 सालों में वह फाईड डेड हो गई। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में मनेन्द्रगढ़ में कैंसर टर्सरी केन्द्र खोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- यह बह्त बड़ी बात है। श्री रामकुमार यादव जी।

प्रश्न संख्या: **05** XX XX

बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्य

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. (*क्र. 775) श्री विक्रम मंडावी : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बीजापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 में दिनांक 10 जनवरी, 2024 तक स्वास्थ्य विभाग (छ.ग.मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन) द्वारा किन-किन मदों से कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं ? (ख) कार्यों का नाम एवं स्वीकृति राशि सहित वर्षवार विकासखण्डवार पंचायतवार जानकारी देवें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : **(क) एवं (ख)** जानकारी ³संलग्न प्रपत्र अनुसार।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय लोक स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रश्न किया था कि बीजापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 में दिनांक 10 जनवरी, 2024 तक स्वास्थ्य विभाग (छ.ग.मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन) द्वारा किन-किन मदों से कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं ? उन्होंने इसकी सूची उपलब्ध करवायी है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहता हूँ कि वहां निर्माण कार्य में कितने काम पूर्ण हैं और कितने काम अपूर्ण हैं? माननीय मंत्री जी, इसकी जानकारी देंवे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चन्द्रपुर विधान सभा में स्वास्थ्य स्विधाओं को लेकर ...।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बीजापुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्न किया है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बीजापुर विधान सभा में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ...।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी को अपना प्रश्न क्रमांक बता दीजिए।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न क्रमांक 06 (775) है।

—अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य का प्रश्न क्रमांक 06 है। आप आराम से उत्तर निकाल लीजिए। कोई बहुत जल्दी नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, आप बिल्कुल टेंशन में मत रहिए। आप आराम से पत्ता पलटिए। अभी आधा घण्टा टाईम है।

_

³ परिशिष्ट "तीन"

अध्यक्ष महोदय :- अभी समय है, आप आराम से करिये, जवाब अच्छा दे रहे हैं। आप ऐसे ही जवाब दीजिए। यदि 02 मिनट और समय लगता है तो निकाल लीजिए। इसमें कोई बात नहीं है। आप बढ़िया जवाब दे रहे हैं, आप जवाब दीजिए।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे ख्याल से जांच का और suspend करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इसलिए उस प्रश्न का जवाब ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका आधा काम तो नेता प्रतिपक्ष जी ने कर दिया।

श्री धर्मजीत सिंह :- महंत जी, आप तो आदरणीय इधर थे। इस सत्ता के लालीपाप में कहीं नहीं थे। आप बार-बार खड़े होकर suspend, suspend कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि आप इनको सबको निपटवा देंगे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बीजापुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 के अंतर्गत इन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों की जानकारी मांगी है। उस पर विस्तृत जानकारी परिशिष्ट में दे दी गई है। परंतु माननीय सदस्य ने कार्यों की स्थिति के संबंध में जानकारी चाही है, अभी तक एक भी कार्य पूर्ण नहीं है, पूरे 77 कार्य अपूर्ण हैं।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय मंत्री जी, मैंने यह प्रश्न पूछा था कि कितने कार्य पूर्ण, अपूर्ण हैं। वर्तमान में वहां पर बह्त सारे कार्य अभी भी अपूर्ण हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ण कार्य एक भी नहीं है, जीरो हैं, पूरे 77 कार्य अपूर्ण हैं, 24 कार्य प्रगतिरत हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि एक भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, आप आगे प्रश्न करिये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय विधायक जी आपकी सरकार थी, आप 05 साल में एक भी कार्य पूरा नहीं करवा पाये। आपका क्षेत्र है और एक भी कार्य पूरा नहीं ह्आ।

श्री विक्रम मंडावी :- अभी आपकी सरकार है तो हम चाहते हैं कि आप यह बताईये कि यह कार्य कब तक पूर्ण होंगे या कब तक पूर्ण होने की संभावना है ?

अध्यक्ष महोदय :- अब अगला प्रश्न करिये।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वही कहा है कि यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेंगे, माननीय मंत्री जी, इसका कुछ आश्वासन देंगे?

अध्यक्ष महोदय :- आप यह बता दीजिए कि यह कार्य कब तक पूर्ण होंगे?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी निश्चित समय-सीमा बता पाना कठिन है।

अध्यक्ष महोदय :- चिलये, ठीक है। बहुत बढ़िया। डॉ. चरण दास मंहत जी।

प्रदेश में होटल, मोटल, रिसॉर्ट आदि का निर्माण एवं संचालन [पर्यटन]

7. (*क्र. 683) डॉ. चरण दास महंत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-(क) पर्यटकों की सुविधा के लिए विभाग के अधीन कितने केंद्र/इकाई कहां-कहां, कब से कितनी-कितनी लागत से निर्मित किये गये थे ? इनका संचालन कौन-कौन कर रहा है? कौन-कौन से केंद्र, कब-कब से तथा क्यों बंद हैं? यदि संचालन के लिए निजी पक्ष को दिया गया है, तो दर एवं शर्तें क्या-क्या हैं ? (ख) उपरोक्त केन्द्रों/इकाईयों से 2019-20 से 2023-24 (दिसम्बर) तक कितनी-कितनी आय हुई? कितना-कितना व्यय हुआ तथा कितनी-कितनी लाभ/हानि हुई? (ग) क्या उक्त केन्द्रों/इकाईयों की स्थापना का उद्देश्य पूरा हो रहा है? यदि नहीं तो क्यों ? भविष्य की क्या योजना है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) पर्यटकों की स्विधा के लिए छत्तीसगढ़ टूरिजम बोर्ड के अधीन 42 केन्द्र/इकाई है। उक्त ईकाईयों के नाम, स्थल एवं जिला का नाम, निर्माण वर्ष, निर्माण लागत जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार⁴** है। उक्त इकाईयों के संचालन की स्थिति, बंद होने का कारण, तथा संचालनकर्ता निजी पक्ष/एजेन्सी का विवरण तथा लीज रेंन्ट का विवरण तथा लीज दर तय करने हेत् निर्धारित म्ख्य नियम व शर्ती आदि का विवरण संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ख) प्रश्नांश "क" उल्लेखित इकाईयों से वर्ष 2019-20 से 2023-2024 (दिसम्बर) तक प्राप्त आय, व्यय तथा लाभ/हानि की जानकारी संलग्न प्रपत्र "स" अन्सार है। (ग) उक्त केंद्रों/इकाईयों की स्थापना का उद्देश्यों की पूर्ति वर्तमान में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा 18 इकाईयों के संचालन से की जा रही है, किन्त् इकाईयों के स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति पूर्णतः नहीं हो पा रही है। इसका म्ख्य कारण होटल/मोटल/रिसॉर्ट का व्यवसायिक ढंग से संचालन हेतु पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन की अनुपलब्धता तथा इनका निरंतर रख-रखाव/प्रबंधन इत्यादि से अतिरिक्त वित्तीय भार आता है। उक्त इकाईयों के सफल संचालन हेत् निजी निवेशकों के माध्यम से किये जाने हेत् कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त प्रक्रिया के तहत संचालित एवं असंचालित इकाईयों को 30 वर्ष + 30 वर्ष की दीर्घ अविध हेत् लीज पर दिए जाने हेत् निविदा आमंत्रित की गई जिनमे क्ल 15 असंचालित इकाईयों के लिए लीज धारक का चयन कर 11 इकाईयों का आधिपत्य सौप दिया गया एवं शेष 04 इकाईयों के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष इकाईयों को लीज पर देने हेत् अपफ्रंट प्रीमियम, इएमडी, परफॉरमेंस सिक्य्रिटी एवं वार्षिक लीज रेंट पुनरीक्षित कर अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अनुमोदन उपरांत भविष्य मे शेष इकाईयों को भी लीज पर सौपने की योजना प्रस्तावित है।

_

⁴ परिशिष्ट "चार"

डॉ. चरणदास मंहत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सबसे वरिष्ठ एवं विद्वान मंत्री से प्रश्न पूछ रहा हूं इसलिए आपका संरक्षण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आपको हमेशा संरक्षण रहेगा।

डॉ. चरणदास मंहत :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय धरमलाल कौशिक जी, अजय चन्द्राकर जी, धर्मजीत सिंह जी से भी निवेदन करूंगा कि अपना पूरक प्रश्न भी पूछें और उसमें मुझे संरक्षण प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय :- यह आग्रह आप लोगों से है। आप लोगों को पूरक प्रश्न पूछना है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न पूछने को बोल रहे हैं तो पूछ लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- हॉ, पूरक प्रश्न पूछने का आग्रह हो रहा है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता जी भी संरक्षण मांग रहे हैं तो इधर से मांग रहे हैं।

डॉ. चरणदास मंहत :- बिल्कुल।

श्री राजेश मृणत :- मतलब उधर की यह स्थिति नहीं है कि वह लोग समर्थन देंगे।

डॉ. चरणदास मंहत :- आप प्रश्न देख लीजिए। मेरा सातवें नंबर का प्रश्न है। आदरणीय पूर्व मंत्री जी के जमाने में प्रदेश में होटल, मोटल, रिसॉर्ट बनाये थे, उसकी संख्या 42 थी, आप लोग 42 होटल, मोटल, रिसॉर्ट आदि बनाये थे और उस पर 150 करोड़ रुपये से भी ज्यादा खर्च हुआ था। उसके लिए जमीन सरकार ने दी थी। आप मुझे यह बता दीतिए कि आज वह 42 होटल कहां हैं, उसमें कितने चल रहे हैं, कितने नहीं चल रहे हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस 42 केन्द्र/इकाई में से 18 केन्द्र/इकाई का संचालन छत्तीसगढ़ पर्यटन विकास निगम कर रहा है। 14 केन्द्र/इकाई को संचालन के लिए अनुबंध करके लीज पर दिया गया है और बाकी होटलों को लीज पर देने की कार्रवाई हो रही है।

डॉ. चरणदास मंहत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें उन्होंने 42 केन्द्र का नाम बताया था और यहां जो जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और यहां सिर्फ 24 केन्द्रों की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। 24 केन्द्रों में अभी काम शुरू हुआ है, उसको रीटेंडर कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। यह 24 केन्द्र कहां हैं, जमीन पर हैं, जमीन से ऊपर हैं या वह ऊपर चले गये हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ जमीन पर हैं, कुछ आधे जमीन पर हैं, ऊपर एक भी नहीं गया है।

डॉ. चरणदास मंहत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब वह 24 केन्द्र बिल्कुल साफ हो गये हैं। यह उस श्रेणी में नहीं आता जिसमें आप लोग प्रश्न करना चाहते हैं। इसमें कोई आदमी suspend नहीं होगा। इसमें मंत्री suspend नहीं होगा। आप क्या बात कर रहे हैं ? प्रभु ! ऐसा नहीं है। आप यह बता

सकते हैं कि जिनको लीज पर दिया गया है, उसमें से कुल कितनी राशि वसूल हो गई है ? जिन बचे हुए होटलों, मोटलों को आपने लीज पर दिया है, उनसे आपको कितनी राशि मिली है ? मेरा तो प्वाईन्टेड प्रश्न है। इसमें सस्पेंशन की जरूरत नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, लगभग 2 करोड़ 42 लाख रूपये की राशि मिली है।

डॉ. चरण दास महंत :- मंत्री जी, अब आप यह बता दीजिये कि अभी बचे हुए 42 इकाईयों का भविष्य में क्या उपयोग होगा या वर्तमान में जो इकाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भविष्य कितने दिन का है?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, उसका भविष्य यह है कि आने वाले दो सालों के अंतर्गत में जितने भी निर्माण हुए हैं, उन सभी निर्माणों को हम लीज पर देकर या उसको पर्यटन विकास निगम प्रारंभ कर देगा।

डॉ. चरण दास महंत :- पर्यटन विकास निगम तो मेरे पीछे बैठा हुआ है। अब तक प्रारंभ करना होता तो वह कर दिया होता। आपके पास भी 15 साल का पर्याप्त समय था। 5 साल, 20 साल में नहीं हो पाया तो आने वाले समय में क्या होगा? यदि वह दान योग्य होगा तो किसी ब्राम्हण को दान दे दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- चरण दास जी, आप दोनों सरकार से परेशान हैं। (हंसी)

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, 15 साल में नहीं हो पाया, 5 साल में नहीं हो पाया तो मैं यह कह रहा हूं कि किसी ब्राम्हण को खोजकर उसको दान कर दीजिये। उस मामले को जीरो कर दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- चिलये, जवाब दीजिये। श्री अजय चन्द्राकर :- उप मुख्यमंत्री जी स्वयं ब्राम्हण हैं।

डॉ. चरण दास महंत :- उनके संरक्षण में दे दीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मंत्रियों को सरकारी संपत्तियों को दान करने का अधिकार नहीं है।

डॉ. चरण दास महंत :- अब तो है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर मेरे स्वयं की संपत्ति होती तो मैं दान कर देता, परंतु मैं आपको इस बात को कह देता हूं कि मुझे 10 साल पर्यटन मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला तो पर्यटन को हमने देश और दुनिया के नक्शे के सामने लाया था। आप यह भी जानते हैं कि हमने राजिम कुंभ के नाम से पूरे देश में पहचान बनाई थी। (सत्तापक्ष के सदस्यों के द्वारा मेजों की थपथपाहट) परंतु आप लोगों ने पांच साल में उसको समाप्त कर दिया। हम पुन: छत्तीसढ़ के पर्यटन, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देश और दुनिया तक पहुंचायेंगे। अगले दो सालों में आपको दिखाई देने लगेगा। पहले तो छत्तीसगढ़ के लोग जतमई माता मंदिर को नहीं जानते थे, जटारानी माता मंदिर को नहीं जानते थे,

मैनपाट को नहीं जानते थे। यह हमारे 15 सालों के कामों के कारण ही लोग जानने लगे हैं। आप भी जानने लगे हैं। पहले छत्तीसगढ़ के लोग नहीं जानते थे।

डॉ. चरण दास महंत :- आदरणीय मंत्री जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपने 42 ऐसे होटल बना दिया, जहां आज तक कोई नहीं रहता है। आपके 42 ऐसे मोटल बन गये, जहां कोई जाना पसंद नहीं करता। आपने सुना जगह पर 42 ऐसे होटल बना दिए, जहां लोग रखने और उसको फिर से लीज में लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप इसको भी तो देखिए। आपने पर्यटन को देश नहीं, विदेश में पहुंचा दिया। आप मेरी तरफ से कुछ पूरक प्रश्न करना चाहेंगे तो कर लीजिये?

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपके ही सपोर्ट में पूछ रहा हूं।

डॉ. चरण दास महंत :- मैं इसीलिए बोल रहा हूं। मैंने तो आपसे निवेदन किया हूं। अब चन्द्राकर जी के मुंह क्यों बंद हो गये? कौशिक जी के मुंह क्यों बंद हो गये?

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी आपके प्रश्न के बाद ख्लेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि यह प्रश्न द्र्भावना से पूछा गया हो। यह प्रश्न जनिहत का है। इसलिए जनिहत का है, क्योंकि बह्त से मोटल, रिसोर्ट वगैरह सब बने ह्ए हैं, पर उसका संचालन कौन करे, कैसे होगा या नहीं होगा। उसका संचालन नहीं होने के कारण वह कबाड़ की स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। मैं मंत्री जी से पहला निवेदन यही करूंगा कि पहले आप सरकार के जिला के कलेक्टरों को यह निर्देश कर दीजिये कि वह अपने संसाधन से वहां पर साफ-सफाई करके वहां पर कम से कम व्यवस्था ठीक करें। जैसे सरगांव का रिसोर्ट बह्त अच्छी जगह में है, लेकिन वहां साफ-सफाई नहीं होने के कारण बह्त तकलीफें हैं। लेकिन जो चील्फी का सरोधा दादर रिसोर्ट है, वह बेहतरीन है। आप सरोधा दादर में जाकर रूकिए। वह वुडन कॉटेज है, बह्त अच्छा है। उसमें 50 प्रतिशत छूट भी है। वहां लोग फैमिली सहित रूकते हैं। उसका view बह्त beautiful है। मतलब कुल्लू-मनाली में आ गए हैं, आपको ऐसा लगेगा। कई बार क्या होता है कि टूरिस्ट आते हैं, उनको कई स्विधाएं नहीं मिल पाती है। जैसे कि बीयर बार की सुविधा। (हंसी) मैं ठीक बोल रहा हूं। जब टूरिस्ट का जगह है तो उसमें बीयर बार अनिवार्य है। आखिर होटलों में बीयर बार है या नहीं है। इसलिए उसमें ऐसे हिल स्टेशन टाईप के कुछ बीयर बार और होटल का प्रावधान कराएं। माननीय मंत्री जी, फिलहाल मैं आपको यह सलाह दे रहा हूं कि अगर किसी गांव में कोई कुछ भी नहीं ले रहा है तो वहां की महिला मंडल को दे दीजिये। वहां कम से कम भात-दाल के लिए रसोई घर चलाकर जो रस्ते में खाने-पीने वाले हैं, उनके लिए दे दीजिये। वहां साफ-सफाई का व्यवस्था करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप प्रक्रिया पूरा कर लीजिये। प्रश्न गंभीर है, प्रश्न में दम है। सर, मैं एक मिनट बता दूं। उत्तराखण्ड में इससे भी छोटा-छोटा गढ़वाल और कुमायूं एरिया में टिन वाला रहता है लेकिन वहां पर फुल रहता है तो थोड़ा सिस्टम के लिये आपसे आग्रह है, चूंकि आपने तो कह ही दिया है लेकिन उसमें कर लीजिये और बीयर बार का भी अगर किसी बड़ी जगह में प्रावधान हो तो उस पर भी विचार करिये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें माननीय मंत्री जी से एक विषय पर और कहना चाहता हूं कि जिन स्थानों में यह सरकारी होटल-मोटल होते हैं उनके मुकाबले जो प्राईवेट सेक्टर के होटल हैं वह सर्वाईव कर जाते हैं लेकिन सरकारी क्यों नहीं कर पाते हैं ? मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर एक-बार समीक्षात्मक रूप से विचार करते हुए ऐसी स्ट्रेटजी बनायें ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये उत्तर आ जाये ।

डॉ. चरणदास महंत :- शर्मा जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह भजन के फार्म में या गीत के फार्म में उनको कोई प्रोत्साहन दीजिये ताकि वह जल्दी से कुछ पर्यटन के विकास के साथ-साथ होटल का भी विकास कर सकें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि आप छत्तीसगढ़ की तुलना राजस्थान, उत्तराखण्ड, हिमाचल या केरल से नहीं कर सकते हैं । हमें छत्तीसगढ़ में Tourism को कमाई का साधन मानने की बजाय छत्तीसगढ़ की पहचान बनाने का माध्यम मानना चाहिए । अगर यह Tourism होटल-मोटल नहीं बनते तो शायद आज जो स्विधा मिल रही है वह भी नहीं मिलती इसलिये छत्तीसगढ़ में Tourism को हमको आगे बढ़ाने के लिये स्विधायें देनी पडेंगी । लोगों को सब्सिडी देनी पड़ेगी, लोगों को आमंत्रित करना पड़ेगा। हमारी तो यह भी योजना है कि अगर हम कोई लोकल हवाई जहाज चलाते हैं तो 50 परसेंट उस हवाई जहाज वाले को हम सब्सिडी दें कि अगर 4 यात्री से कम होंगे तो 10 यात्रियों का पैसा हम देंगे । यह जो सोच है कि यदि हमने 50 करोड़ रूपये खर्च किये तो 100 करोड़ रूपये की आय होनी चाहिए । छत्तीसगढ़ में आपको हजार-दो हजार, 10,000 करोड़ रूपये पर्यटन के क्षेत्र में खर्च करने पड़ेंगे और जब 10,000 करोड़ रूपये खर्च हो जायेंगे तो पूरे देश में आपका नाम होगा तब यहां पर्यटक आयेंगे तब आपकी इंकम होगी और जो एक पर्यटक है वह 8 लोगों को रोजगार देता है इसलिये डायरेक्ट बेनीफिट जरूरी नहीं है । आपको जी.एस.टी. मिलता है, आपको Incometax मिलता है । हमारी यह जो सोच है उसी सोच ने, मैं आपसे यह कहता हूं कि हमारी सरकार के समय भी और आपकी सरकार के समय भी Tourism को हमने पैसा कमाने का साधन मान लिया और इसलिये उसके डवलपमेंट के लिये पैसा नहीं दिया और उसके कारण आज यह स्थिति है । Tourism के बारे में हम जब तक ऐसी नीति नहीं बनायेंगे कि लोगों को आकर्षित करने के लिये क्या-क्या Investment करना चाहिए इसलिये हमने प्राईवेट लोगों को लाना श्रूक किया और जब से प्राईवेट लोग आना शुरू हुए हैं तो हमारा खर्च कम हुआ है और उन्होंने डवलप करना शुरू किया है । आने वाले समय

में हम ऐसी पॉलिसी बनायेंगे कि पी.पी.पी. मॉडल पर Private Investment के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के Tourism को एक पहचान दे सकें यह हमारी योजना है और आने वाले 3 महीनों में आपको जो एक नयी पर्यटन नीति है वह भी आपको यहां पर दिखायी देगी ।

अध्यक्ष महोदय :- महंत जी, आप संतुष्ट हैं ? बस समाप्त करिये । डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संतुष्ट हूं । मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय :- चिलये, सुझाव दीजिये ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, आप विद्वान हैं । आपने पर्यटन को खूब देश-विदेश तक फैलाया । मुझे उसमें कहीं कुछ नहीं कहना है । यदि आप पर्यटन नीति बना रहे हैं तो मेरा एक सुझाव है कि 42 के 42 में से 24 तो ठीक-ठाक हैं । आप एक बस सर्किट बनाईये और उस बस सर्किट में यात्रियों को दिखाइये । जिनको बस्तर जाना हो तो बस्तर जायें, कोण्डागांव जायें, आपके कबीरधाम में रूकें । एक-एक दिन का प्रोग्राम बनाते जाईये, दर्शन कराईये तो यह जिंदा भी हो जायेगा । आपका मोटल भी चलेगा, होटल भी चलेगा और जिसकी चिंता धर्मजीत भैया को है । उसको यह कह दीजिये कि जिसको पीना है वह घर से ले जायें । मेरा आपसे यह निवेदन है कि वहां आप बीयर बार मत दीजियेगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं अपने लिये नहीं बोल रहा हूं । (हंसी) मैं Tourist लोगों के लिये बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- वह बोल रहे हैं कि घर से ले जायें । (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे न ।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत प्रश्न हो गये । चलिये एक छोटा प्रश्न करिये ।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को इस विषय पर एक और चिंता करनी चाहिए । चूंकि पिछली सरकार में बिना अनुमित के, बिना राज्य शासन के कई जगह OYO Centre का संचालन किया जा रहा था । पिछले शासनकाल में कोई ऐसी भी चीज बिना राज्य शासन की अनुमित के चल रहा था तो इसकी चिंता करना भी आवश्यक है कि यदि यह बिना अनुमित के चल रहा था तो उसमें रोक लगाने का भी काम करना पड़ेगा । जितने पर्यटन स्थल हैं, हमारी सरकार ने जितना सजाकर दिया था । आदरणीय नेता जी, पिछले 5 सालों में पूरी गंदगी मचाने का काम किया गया है, कबाड़ करने का काम किया गया है, कबाड़ करने का काम किया गया है, चें पिछले 5 साल में हुए हैं तो इन पर्यटन स्थलों में ये OYO सेंटर किसके माध्यम से चलाये जा रहे थे, ये भी जांच का विषय है और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस OYO सेंटर को

लेकर गंभीरता से जांच करने की आवश्यकता है और इस सरकार में ऐसा कोई भी OYO सेंटर संचालित न हो, इसके लिए भी विचार करना आवश्यक है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप बोलिए।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अध्यक्ष महोदय, में माननीय पर्यटन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने अपने कार्यकाल में जो मोटल्स बनाये थे, मोटल्स के कई लोकेशन्स ऐसे थे, जहां पर अभी भी कोई टूरिस्ट नहीं जायेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि छत्तीसगढ़ में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हमारे पास 4 नेशनल पार्क्स हैं। हमारे पास 6 वाटर बॉडिज हैं। पर पिछले 20 सालों में जब से छत्तीसगढ़ बना है, पर्यटन को हमेशा दोयम दर्जे में रखा गया है। आदरणीय मंत्री महोदय, पर्यटन को बढ़ावा देने की आपकी सोच बहुत अच्छी है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि क्या भविष्य में क्योंकि जब तक प्राइवेट प्लेयर्स इस पर्यटन उद्योग में नहीं आयेंगे, हम पर्यटन को आगे बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। आगे की पर्यटन नीति में हम क्या प्राइवेट प्लेयर्स को उन जगहों पर सब्सिडाइज रेट पर जगह देंगे, जहां पर वे अपने होटल्स, मोटल्स को डेव्लप कर सकें ताकि आने वाले टूरिस्ट को फायदा हो सके। हमारा लैण्ड लॉक स्टेट है। हम 7 राज्यों से घिरे हुए हैं। पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर मैं फिर से निवेदन करूंगा कि पर्यटन मंत्री के रूप में आपके कार्यकाल में इसे आगे बढ़ायें, जिस तरीके से हमारे कार्यकाल में पर्यटन नीति बनी थी, उसका implementation नहीं हो पाया, इसको आगे कैसे बढ़ाया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन जी, आप एक लाइन में जवाब दे दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का, माननीय हमारे पूर्व पर्यटन मंडल के अध्यक्ष जी का, माननीय धर्मजीत जी का, भिलाई के हमारे माननीय विधायक जी का, माननीय अनुज शर्मा जी का, सबके अच्छे सुझाव हैं और हम नई पर्यटन नीति में प्राइवेट investment करके छत्तीसगगढ़ के टूरिज्म को बढ़ावा देने की हमारी कोशिश होगी, इस बात का मैं पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, अजय जी।

रामवनगमन परिपथ अंतर्गत चिन्हांकित स्थलों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति [पर्यटन]

8. (*क्र. 54) श्री अजय चंद्राकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) दिनांक 30 नवबंर ,2023 की स्थिति में रामवनगमन परिपथ अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितने

स्थानों का चयन किया गया है तथा इसकी चयन समिति में कौन-कौन अध्यक्ष व सदस्य थे तथा किस आधार पर इन स्थलों का चयन किया गया? (ख) उक्त परिपथ अंतर्गत किन-किन स्थलों पर, किनकी-किनकी प्रतिमा लगायी गयी है व कितनी प्रतिमा लगाई जाना शेष हैं? उन प्रतिमाओं का डिजाईन, ड्राईंग, एसओआर, कार्यावधि व प्रतिमा की दिशा ,उनका स्वरूप एवं उसकी लाईफ का निर्धारण किस प्रकार किया गया? इन कार्यो के लिये टेंडर कब हुआ? कार्य एजेंसी कौन-कौन है? उसका नाम, पता सहित बतायें? जो कार्य एजेंसी तय की गयी हैं, क्या उनका कार्य अनुभव इन कार्यो हेतु था? यदि नहीं, तो किस आधार पर उन एजेंसियों को तय किया गया? (ग) उक्त परिपथ अंतर्गत चिन्हांकित स्थलों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति क्या है? लगाये गये या लगने वाली प्रतिमा हेतु कितनी राशि की वित्तीय व्यवस्था की गयी थी तथा किन-किन प्रतिमा के लिये, किन-किन कार्यों हेत्, कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) दिनांक 30 नवम्बर 2023 की स्थिति में राम वनगमन परिपथ अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 10 स्थलों के विकास का निर्णय लिया गया। स्थल चयन हेतु गठित चयन समिति के अध्यक्ष, सदस्य व आधार की जानकारी संलग्न परिशिष्ट † पपत्र "अ" अनुसार है। (ख) उक्त परिपथ के अंतर्गत राजिम, शिवरीनाराण, सीतामढी-हरचौका, रामगढ, मुकुन्दपुरनगरी और चन्दखुरी में प्रभु श्री राम की प्रतिमा लगाई गई है, मुकुन्दपुर नगरी में सप्तऋषियों की प्रतिमा एवं शिवरीनारायण में प्रभु श्रीराम, लक्ष्मण जी एवं माता शबरी की प्रतिमा लगाई गई है। प्रतिमाओं का डिजाईन ड्राईग, एस.ओ.आर., स्वरूप अनुबंधित एजेंसी टी.सी.आई.एल एवं वापकास द्वारा तैयार किये गये डी.पी.आर. के आधार पर किया गया है। इन कार्यों के लिये टेंडर, कार्य एजेंसी, एजेन्सी का कार्य अनुभव तथा एजेन्सी चयन आधार की जानकारी संलग्न प्रपत्र "व" अनुसार है। (ग) उक्त परिपथ अंतर्गत चिन्हांकित स्थलों में राशि रू. 81.00 करोड़ व्यय किया गया है। चिन्हांकित 10 स्थलों में से 05 स्थलों में कार्य पूर्ण हो चुके है, शेष 04 स्थलोंमें मार्च 2024 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। एक अन्य स्थल (जगदलपुर) के कार्यों का क्रियान्वयन कलेक्टर, बस्तर (जगदलपुर) के द्वारा किया जा रहा है। चिन्हांकित स्थलों में लगायी गयी प्रतिमा की राशि का विवरण संलग्न प्रपत्र "स" अनुसार है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मेरा जो मुंह खुलता है न, शासन चलाने की भूपेश Doctrine में खुलता है। मैं छोटे-मोटे Doctrine में बात ही नहीं करता। माननीय अध्यक्ष महोदय..।

डॉ. चरण दास महंत :- आप अगला प्रश्न पूछ रहे हैं क्या?

श्री अजय चन्द्राकर :- हां, अगला प्रश्न पूछ रहा हूं।

डॉ. चरण दास महंत :- मैंने मेरा पूरक प्रश्न पूछने का निवेदन किया था। उन्हें भी कहा था कि आप भी पूरक प्रश्न पूछ लें।

^{5 †} परिशिष्ट "पांच"

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा नाम पुकार दिये न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में Telecommunications Consultants India Ltd., Water and Power consultancy services Ltd. मूर्ति बनाने से जिसका दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है, उसे रामवनगमन परिपथ की मूर्ति बनाने का ठेका मिला है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ये है शासन चलाने की Doctrine, जिसमें मेरा जोरदार मुंह खुलता है। यही बोधघाट परियोजना बना रही थी और यही मूर्ति लगा रही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप समझ रहे हैं? आपने उत्तर दिया है कि ड्राइंग डिजाइन एस.ओ.आर., स्वरूप अनुबंधित एजेंसी टी.सी.आई.एल. एवं वापकॉस द्वारा तैयार किये गये हैं। तो मूर्ति लगाने के ड्राइंग डिजाइन और एस.ओ.आर. विशेष रूप से क्या थै?

डॉ. चरण दास महंत :- यह मुझसे पूछ रहे हैं या मंत्री जी से पूछ रहे हैं? (हंसी) श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष के माध्यम से मंत्री जी से पूछ रहा हूं। (हंसी) अध्यक्ष महोदय :- अभी आपका अवसर नहीं है। डॉ. चरण दास महंत :- नहीं, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया, इसलिए बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, बैठिए। (हंसी)

डॉ. चरण दास महंत :- इनकी आदत इतनी खराब है कि कभी चेयर की ओर बात ही नहीं करते और न चेहरा रखते। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- भैया, बात तो कर रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपसे प्रेरणा ले रहे हैं। अध्यक्ष जी के माध्यम से मंत्री जी से पूछ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बृजमोहन जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, टी.सी.आई.एल. और वापकॉस है, उसको योजना बनाने के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन्हें दिया गया था और साथ में उन्हीं को कि हमें ये-ये काम करवाना है और इन कामों के लिए आप जो बेस्ट वास्तुकार हो सकते हैं, बेस्ट मूर्तिकार हो सकते हैं, उन्हें आप अनुबंधित करिए और उनके माध्यम से आप बनवाइए, ऐसी उसमें प्रक्रिया अपनायी गयी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने माननीय मंत्री जी से बहुत स्पेशिफिक प्रश्न पूछा है। आपने उत्तर भी दिया है कि एस.ओ.आर. ड्राईंग डिजाइन तैयार की गई है। तो मूर्ति बनाने के लिए एस.ओ.आर. और ड्राईंग क्या थी? क्योंकि कई मूर्ति ऐसी हैं जो राम भगवान की मूर्ति ही नहीं लगती। इसलिए आपको इस बात को बताना पड़ेगा कि एस.ओ.आर. क्या था ? कौन से दर पर उन्होंने मूर्ति बनायी है? अभी रामलला की मूर्ति लगी। 3 लोगों ने टेंडर भरा, 3 लोगों ने बनाकर दिया कि इतने साल चलेगा। इतनी उसकी आयु होगी। इस पत्थर से बनेगा। उसमें सारा कुछ निर्धारित था। तो आप कम से कम ड्राइंग और एस.ओ.आर. किस आधार पर निर्धारित किया गया था, वह कौन से एस.ओ.आर. और ड्राइंग में बना, यह बता दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि इसका डी.पी.आर., टीसीआईएल ने और वापकॉस ने तैयार किया और शासन ने उन्हें बता दिया कि इतने स्थानों पर मूर्ति लगाना है, इतने स्थनों पर डेव्हलपमेंट करना है । उसके लिए आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए । क्योंकि इसमें इन दोनों कंपनियों को ही पूरा अधिकार दिया गया था । ड्राइंग डिज़ाइन भी उन्हें ही बनाना है, टेंडर भी उन्हें ही करना है, एलॉटमेंट भी उन्हें ही करना है । उसके लिए केवल उनकी कन्सल्टेंसी फीस, जो उसके कांट्रेक्टर होंगे, जो निर्माण करेंगे, उसका पैसा दिया जाएगा, उसको पेमेंट करेंगे और उसका हिसाब देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप परिशिष्ट देख लीजिए । एस.ओ.आर. जानना इसलिए जरूरी है कि हर मूर्तियों का रेट अलग-अलग है इसलिए उसका एस.ओ.आर. जानना पड़ेगा कि कौन से पत्थर से बनाए, कौन सी लागत से बनाए, उसके डिटेल्स में तो होगा, उनको बताना चाहिए । कहीं पर 9 लाख में, कहीं 4.5 लाख में, कहीं 34 लाख में, कहीं 70 लाख में मूर्ति बनी है, कहीं 69 लाख में बनी है । कितनी हाईट की मूर्तियां हैं, शासन के पास उसका एस.ओ.आर. तो जमा होगा ? कितनी हाईट की होगी, कौन सी मुख मुद्रा होगी, कौन सी मुद्रा होगी, कुछ तो होगा ? महात्मा गांधी की फोटो को वहां जाकर लगा दिया है । यह तो आपको बताना चाहिए कि कौन सा एस.ओ.आर. है क्योंकि प्रत्येक मूर्ति की दर अलग-अलग है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी भी मंत्री रहे हैं । बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो नॉन एस.ओ.आर. के होते हैं और नॉन एस.ओ.आर. के जो आइटम होते हैं उसमें जिसको यह काम दिया गया, उन्हीं के द्वारा यह तय किया गया कि कैसी डिजाइन होगी, कैसी मूर्ति होगी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय महोदय, आपने उत्तर में ही दिया है कि एस.ओ.आर., टी.सी.आई.एल. और वापकॉस ने तय किया है तो एस.ओ.आर. की जानकारी शासन के पास होनी चाहिए । चलिए, दूसरी बात, आपने टीप में लिखा है कि डॉ. रामअवतार शर्मा और हेम् यदु की किताबों से राम वन गमन पथ का चयन किया गया । आप उस रिपोर्ट को टेबल करेंगे क्या जिसके अनुसार राम भगवान, चंदखुरी और चंपारण गए थे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चंपारण का काम हमारी मूल योजना में नहीं था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, आपकी मर्जी से कैसे चलेगा, कहीं पर राम भगवान नहीं गए हैं । आपको इतिहास से छेड़छाड़ करने की अनुमित किसने दे दी ? मायथोलॉजी से छेड़छाड़ करने की अनुमित आपको किसने दे दी । आप इसको टेबल करेंगे क्या ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर । श्री अजय चन्द्राकर :- कोई भी आदमी छेड़छाड़ करे और आप उसको स्वीकार कर लेंगे, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी रहे हों ? आप दोनों शोध को टेबल करेंगे क्या, चंदखुरी और चंपारण वे गए थे, इस रिपोर्ट को टेबल करेंगे क्या, तािक प्रदेश की पूरी जनता जाने कि प्रदेश की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है फिर चाहे वह मुख्यमंत्री रहें या कोई भी रहें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपकी जो चिंता है उस चिंता से मैं भी वाकिफ हूं । मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंपारण को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राम वन गमन पथ में जोड़ा गया था । यह हेमू यदु की किताब में भी नहीं है, यह राम अवतार शर्मा जी की किताब में भी नहीं है । यह मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जोड़ा गया था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुनिए साहब, यह गंभीर विषय है । मैं कह रहा हूं कि मेरे निर्देश पर या अध्यक्ष जी निर्देश दें तो कही पर भी आप प्रतिमा लगा देंगे । ऐसा कैसे हो जाएगा ? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने जो काम करवाया है वह कौन-कौन से मद से करवाया है इसकी जानकारी दे सकते है क्या और उसका एकाध जगह सोशल ऑडिट करवाएंगे क्या ? मैं भी चलूंगा और आप भी चलें । चंदखुरी का सोशल ऑडिट करवा लें, शिवरीनारायण का सोशल ऑडिट करवा लें । विधायक की समिति से सोशल ऑडिट करवा लें ।

डॉ. चरणदास महंत :- समय कम है ज़रा ज़ोर से प्रश्न पृछिए, समय खत्म हो रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे, आप तो इतिहास बनाते हो, जहां गए नहीं, वहां भी पैसा खाने के लिए ।

डॉ. चरणदास महंत :- हमें भी शामिल कर लो ना ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है और चंदखुरी में प्रभु राम की जो प्रतिमा लगाई गई, उसके मामले को लेकर भी लोगों में बहुत नाराज़गी है । मैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अजय चन्द्राकर जी हमारे विद्वान् सदस्य हैं । उनकी अध्यक्षता में एक सोशल ऑडिट कमेटी का गठन करता हूं, वे इसकी जांच करेंगे (मेजो की थपथपाहट)। मुझे लगता है कि इसके बाद और कोई प्रश्न नहीं बचता है ।

अध्यक्ष महोदय :- बढिया । उस मूर्ति के नीचे भगवान् राम का नाम लिख दीजिए ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न न हो ।

डॉ. चरणदास महंत :- उस सोशल ऑडिट में इधर के लोगों को भी शामिल कर लीजिए ।

श्री अजय चन्द्रांकर :- आप और कोई जगह बता दीजिए, मूर्ति लगवा देंगे, अच्छा चांस है, बहुत अवसर है पैसा खाने का ।

डॉ. चरणदास महंत :- सोशल ऑडिट में विपक्ष के लोगों को भी रखिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हां, विपक्ष के लोगों को भी रखेंगे । अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)



समय :

12:00 बजे

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था आय-व्ययक के उपस्थापन के पश्चात् माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों के लिए सेंट्रल हॉल में की गई है । कृपया, सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक का उपस्थापन आज मध्याहन 12.30 बजे माननीय वित्तमंत्री जी द्वारा किया जाएगा । अत: सभा की कार्यवाही मध्याहन 12.30 बजे तक के लिए स्थगित् ।

(12.00 से 12.30 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12:32 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई, उनके कार्यकाल का पहला बजट आ रहा है। (मेजों की थपथपाहट)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- स्वागत है। (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ का पहला प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक क्षेत्र में काम करते-करते जन सेवा में आ करके आज छत्तीसगढ़ की कल्याणकारी योजनाओं का बजट प्रस्तृत कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. चरण दास मंहत :- बिल्कुल देखेंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं देखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं, माननीय विष्णु देव साय मुख्यमंत्री जी का पहला बजट आ रहा है तो बजट उनके पास आकर पढ़ लेते, कोई जरूरी था कि उतना दूर जाकर पढ़ें। यहां लगाने में क्या दिक्कत थी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी पढ़ तो अंदर से ही रहे हैं ना, बाहर से थोड़ी ना पढ़ रहे हैं।

डॉ. चरण दास मंहत :- मैं कह रहा हूं, अगर उनका बजट है तो पास से पढ़िए ना।

श्री अजय चंद्राकर :- चलिए, आज आप इधर आकर बैठ जाईए।

डॉ. चरण दास मंहत :- आ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक का उपस्थापन । श्री ओ.पी. चौधरी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्योंकि अभी तक विधान सभा में instrument का प्रदर्शन या उसको देखकर पढ़ने की परंपरा नहीं रही है और ना विधान सभा में इस प्रकार का कोई आदेश है। मैं वित्त मंत्री जी के टेबल में देख रहा हूं कि वे लैपटॉप लेकर खड़े हैं। मैं समझता हूं कि विधान सभा में अभी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं दी गयी है। कृपा करके जो पुरानी परंपरा है, उसके अनुरूप ही उसका वाचन करें, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, instrument के प्रदर्शन पर रोक है, उसको देखकर पढ़ने पर रोक नहीं है। वह प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। वैसे भी हम विधान सभा में पेपरलेस की ओर बढ़ रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम विधान सभा में पेपरलेस की ओर बढ़ रहे हैं। माननीय चरण दास महंत जी जब अध्यक्ष थे तो आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रश्न ऑनलाईन लगाना श्रू किए। पूरी विधान सभा Digitalization की ओर बढ़ रही है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था आ जाए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ठीक है।

श्री भूपेश बघेल :- क्योंकि अभी तक मान लीजिए मोबाईल में कोई तथ्य है, यदि हम उसमें पढ़ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है तो उसमें कोई आपित नहीं है, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आने वाले समय में मैं समझता हूं वह ठीक है। हम तो पेपरलेस की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग पुराने ढर्र में फिर जा रहे हैं। आप फिर नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी में आ गए। (मेजों की थपथपाहट) (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- पूरी दुनिया डिजीटल इंडिया की ओर बढ़ रही है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी, छत्तीसगढ़ की पहचान है। (व्यवधान) हम इसका विरोध करते हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अपमान हो रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप छत्तीसगढ़ के साथ खेल खेल रहे हैं।(व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यह पहले तय होना था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- धरमलाल कौशिक जी, प्लीज बैठिये।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने यह कहीं पर नहीं कहा कि गोबर खरीदी भी ऑनलाइन होती थी।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये।

श्री राजेश मूणत :- आपकी तो ऑनलाइन को ऑफलाइन करने की आदत है।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये। माननीय वित्त मंत्री जी ने मुझसे आग्रह और निवेदन किया था, मैंने उसको स्वीकार कर लिया है और मैंने उनको अन्मति दी है। (मेजों की थपथपाहट)

समय :

12.36 बजे

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक का उपस्थापन

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की जनता-जनार्दन ने कुशासन के खिलाफ मुहर लगाकर हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। ऐतिहासिक जनादेश द्वारा प्रकट किये गये स्नेह और विश्वास के लिए हम छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों का हद्य की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्राण प्रतिज्ञा करते हैं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, हमारे चारों ओर चुनौतियों का घना अंधेरा है। महिलाएं कानून-व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति की शिकार रहीं। युवा मन अविश्वास और आशंकाओं से ग्रसित रहा। पिछले सालों में प्रशासनिक तंत्र पटरी से उतरा रहा और राजकीय खजाना हमें खाली मिला है। पर हम अंधेरों के बीच उजाले की तलाश करने की ताकत रखते हैं। चुनौतियों का घना अंधेरा है। (मेजों की थपथपाहट) कोई भी सार्थक व्यक्ति, कोई भी सार्थक समाज, कोई भी सार्थक सरकार कभी अंधकार के साम्राज्य को विजयश्री का तिलक नहीं लगा सकता है। चहुंओर चुनौतियों से घिरे होने के बावजूद हम एक लक्ष्य और सपना देखने की ताकत रखते हैं। चुनौतियों का अंधेरा हमें स्वर्गीय बच्चन जी की इन पंक्तियों का स्मरण कराता है:-

पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है, है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, यह हमारा और हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि एक ओर हम लोग 500 सालों के संघर्ष के बाद श्री रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में होते हुए देख पा रहे हैं और हमारी पीढ़ी का यह भी सौभाग्य है कि देश के अमृत काल में भारत को दुनिया का सुपर पावर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किये जा रहे क्रांतिकारी कार्यों को हमारी पीढ़ी देख रही है और उसमें सहभागिता भी निभा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अथक ऊर्जा आज यदि हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है तो सहज-सरल मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी का कुशल नेतृत्व हमारी ताकत बनकर हमारे साथ है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, आज देश अमृत काल में नई ऊर्जा और नये विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया आज भारत की ओर निहार रही है। विकसित भारत का सुस्पष्ट लक्ष्य सबके सामने है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ के विकास को ग्रहण लग गया था। भ्रष्ट और स्वार्थपरक ताकतों ने छत्तीसगढ़ को दबोच कर रखा था। चिंता होती थी कि भारत की इस विकास यात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ का क्या होगा ? लेकिन लोकतंत्र की ताकत ने इन नकारात्मक शक्तियों को पराजित कर दिया। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की जनता की उंगलियों पर लगी स्याही ने छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के नये रास्ते खोल दिये हैं। विकास यात्रा का कृष्ण पक्ष समाप्त हो चुका है और शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो चुका है। विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में सुशासन का सूर्योदय हो चुका है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, किसी सरकार के बजट को महज उसके आय-व्यय के लेखा-जोखा के रूप में ही नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि वह किसी सरकार के भविष्य के विजन का भी एक दस्तावेज होता है, जो दशा और दिशा को निर्धारित करता है। उसे विजन डॉक्यूमेंट के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के इस मोड़ पर सवाल उठता है कि हम छत्तीसगढ़ को आगे कहां लेकर जाना चाहते हैं। हमारी कमजोरियां क्या हैं ? हमारी ताकतें क्या हैं ? Management में एक SWOT Analysis होता है अर्थात् Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. जब हम अपने छत्तीसगढ़ का SWOT Analysis करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ के कौन-कौन से पक्ष उभर कर सामने आएंगे ? इसका analysis जरूरी है। देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करके विकसित राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित होगा तब हमारा छत्तीसगढ़ देश के अन्य राज्यों के साथ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करता हुआ कैसे आगे बढ़ेगा ? यह हमारे सामने एक चुनौती है।

इसके लिए एक स्पष्ट सपना, एक स्पष्ट लक्ष्य जरूरी है। उस लक्ष्य तक पहुंचने की रणनीति जरूरी है। एक रोड मैप जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमने तय किया है कि छत्तीसगढ़ वर्ष 2047 तक कैसे एक विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनेगा, इसका दृष्टि-पत्र (Vision Document) हम तैयार करेंगे। इस दृष्टि-पत्र का नाम होगा :-"अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विजन @ 2047" (मेजों की थपथपाहट)

1 नवम्बर, सन् 2000 को भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य को बनाया था और इसी 1 नवम्बर को इसी साल सन् 2024 में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को विकासशील से विकसित राज्य बनाने हेतु यह विजन डॉक्यूमेंट जो "अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विजन @ 2047" डॉक्यूमेंट होगा, उसे हम इस राज्य की जनता को समर्पित करने का काम करेंगे । (मेजों की थपथपाहट)

हमने बनाया है, हम ही सँवारेंगे ।।

अध्यक्ष महोदय, यह छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति हमारा किमटमेंट है, हमारे सरकार की प्रतिबद्धता है। (मेजों की थपथपाहट) कहा जाता है कि कोई भी सार्थक व्यक्ति के लिए कोई भी मंजिल आखरी मंजिल नहीं होती। हर मंजिल एक पड़ाव होता है अगले मंजिल तक आगे बढ़ने के लिए। इसी

दर्शन के साथ मोदी जी कहते हैं कि हम बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य बनाते हैं । यह मोदी जी का विजन है । 2047 के दीर्घकालीक विजन तक पहुंचने से पहले हमें मध्यम अविध का अर्थात् मिडटर्म टारगेट भी बनाने होंगे । हम छत्तीसगढ़ के लिए तय कर रहे हैं कि 2047 तक हमारा छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ होगा । उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा मिडटर्म टारगेट क्या होगा, वह भी हम निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं । जैसे मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए मध्यम अविध के टारगेट के रूप में 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन डॉलर इकानॉमी का लक्ष्य रखा है । उन्होंने अगले 5 सालों के लिए भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का मध्यम अविध टारगेट रखा है। अध्यक्ष महोदय, हम भी इसी तरह का एक मध्यम अविध लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे छत्तीसगढ़ की जी.एस.डी.पी. लगभग 5 लाख करोड़ है । इसे आने वाले 5 सालों में 2028 तक 10 लाख करोड़ करना हमारा बहुत ही मध्यावधि (Mid term) लक्ष्य है । (मेजों की थपथपाहट) आप पिछले 5 सालों की तुलना करेंगे तो यह लक्ष्य बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन फिर भी इस बड़े लक्ष्य को हम स्वीकार कर रहे हैं और इस चुनौती के लिए आदरणीय विष्णु देव साय के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे । यह मध्यावधि लक्ष्य, देश को दुनिया की तीसरा बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के मोदी जी के महायज्ञ में हमारा योगदान होगा । मोदी जी से "सहकारी संघवाद" (Cooperative Federalism) के सिद्धान्त पर चलते हुए हम केन्द्र का सहयोग भी प्राप्त करेंगे और देश के विकास यात्रा में अपनी महती भूमिका भी निभाएंगे । छत्तीसगढ़ अब केन्द्र से टकराव वाले पिछले 05 वर्षों के मॉडल के स्थान पर डबल इंजन की सरकार में संघ- राज्य समन्वय के विकास का नया अध्याय लिखेगा । (मेजों की थपथपाहट) इन 5 सालों के अत्यंत मध्यावधि लक्ष्य जो जी.डी.पी. को केवल 5 सालों में दोगुना करने का लक्ष्य जो हम निर्धारित कर रहे हैं ।

इस मध्याविध लक्ष्य के तहत 10 लाख करोड़ की जी.डी.पी. तक पहुंचना चाहते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए हम आधारभूत रणनीतिक स्तम्भ के रूप में (Fundamental Strategical Pillars) के रूप में 10 स्तम्भों की पहचान किये हैं और उसको मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं:-

- 1. GYAN : हमारे आर्थिक विकास का केन्द्र बिन्दु होगा-ज्ञान । (Focus of our Economic Development)
- 2. तकनीकी आधारित रिफार्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास (Rapid Economic Growth through Technology driven Reforms Governance)
- 3. तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना (Maximum CAPEX)
- 4. प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल

(Optimum utilization of Natural Resources)

- 5. अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नयी संभावनाओं पर जोर (Emphasis on new possibilities of service sector of the economy)
- 6. सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना (Ensuring private investment)
- 7. बस्तर-सरगुजा की ओर भी देखों (Focus on Bastar-Sarguja)
- 8. DDP: डिसेंट्रेलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स (विकेन्द्रीयकृत विकास पॉकेट) (DDP: Decentralized Development pockets)
- 9. छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास (Promoting Chhattisgarhi culture) (मेजों की थपथपाहट)
- 10. क्रियान्वयन का महत्व

(Importance of Implementation)

इन 10 पिलर्स को मैं थोड़ा व्याख्यायित करना चाहता हूं । हमारा जो पहला पिलर है-

1. GYAN: हमारे आर्थिक विकास के केन्द्र बिन्दु :-

(Focus of our Economic Development)

हमारे आर्थिक विकास का केन्द्र बिन्दु होगा, वह ज्ञान होगा । नॉलेज तो होगा ही, मोदी जी की विजनरी नजर समाज को चार स्वरूपों में देखती है । हमारे इस ज्ञान का अर्थ है-

- G अर्थात् ~ गरीब
- Y अर्थात् ~ युवा
- A अर्थात् ~ अन्नदाता
- N अर्थात् ~ नारी (मेजों की थपथपाहट)

ज्ञान के माध्यम से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित हमारा आर्थिक विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है पिछले 05 वर्षों में हमारे छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार ने इन चारों समूहों के साथ अन्याय किया है। न केवल गरीबों के छत के अधिकार को छीना गया, यूरिया, डी.ए.पी. में कालाबाजारी हुई, 02 रूपए में गोबर खरीदकर गुणवत्ता विहीन कम्पोस्ट खाद के नाम पर जबरन 10 रूपए में उसे बेचा गया। किसानों के संदर्भ में, अनेक प्रकार की लूटें हुई, मैं किन-किन लूटों की बात करूँ ? क्या-क्या बताया जाए ? अध्यक्ष महोदय, माताओं-बहनों को इन्होंने

500 रूपए प्रति माह अर्थात् 6000 रूपए साल का देने का वादा किया था, मगर किसी को 06 रूपए तक नहीं मिला ।

अध्यक्ष महोदय, युवाओं के साथ भी बहुत अन्याय हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बड़े सपने लेकर हमारे युवा आये थे, उनके साथ अन्याय हुआ है। इस सन्दर्भ में नेल्सन मंडेला जी का एक quotation को code करना चाहता हं :-

" Destroying any nation does not require the use of atomic bombs or the use of long range missile. It only requires lowering the quality of education and allowing cheating in the examinations by the students."

अर्थात् " किसी देश को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए बम, बारूद, मिसाईल की ही जरूरत नहीं होती है। शिक्षा की गुणवत्ता को खराब कर देना और परीक्षाओं में भ्रष्टाचार ही किसी देश को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होता है।" यह विजनरी लीडर नेल्सन मंडेला ने कहा है।

अध्यक्ष महोदय, पी.एस.सी. की प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षाओं में युवाओं के साथ अन्याय हुआ, जिसमें हमारी सरकार ने सी.बी.आई. जांच का निर्णय लिया है। अभी-अभी ई.ओ.डब्ल्यू. में भी एफ.आई.आर. दर्ज हुआ है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, गरीब, किसान, युवा और महिलाएं, ये 4 हमारे आर्थिक विकास के केन्द्र बिन्दु रहेंगे। उन्हें केन्द्र बिन्दु में रखते हुए उन्हें उर्जा और सही दिशा, अवसर प्रदान देकर हम प्रदेश की आर्थिक उन्नित में इनकी सहभागिता स्निश्चित करेंगे, यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है।

2. तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास (Rapid Economic Growth through Technology driven Reforms and Governance) :-

अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा पिलर है वह है तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटिलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, कंप्रिहेंसिव सिस्टम डेवलपमेंट, सैटेलाईट बेस्ड कम्युनिकेशन से संचालित हो रही है। हम शासन और प्रशासन में तकनीक के इस्तेमाल पर पूरा जोर देंगे। इससे नागरिक सुविधाओं में पारदर्शिता आयेगी और समस्याओं का तीव्र समाधान भी होगा। इससे हम मोदी जी के "न खाऊंगा, 'न खाने दूंगा" की भावना को चरितार्थ कर पायेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार द्वारा कोयला पर तकनीक आधारित ऑनलाईन रायल्टी सिस्टम को हटाकर लाल फीताशाही मैनुअल सिस्टम को लागू किया गया था। हमारी सरकार प्रशासनिक काम-काज की प्रक्रिया में ऐसे कपटपूर्ण मैनुअल हस्तक्षेपों पर पूर्ण विराम लगायेगी। तकनीक आधारित प्रयोगों के माध्यम हम सरकार के खजाने के लीकोजों (Leakages) को रोकेंगे और कर की दर में वृद्धि बिना, हम पारदर्शी तकनीको आधारित करारोपण को अपनाकर सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखायेंगे और ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, हमने पूरी ईमानदारी के साथ शासन के प्रत्येक विभाग के साथ चर्चा करते हुए प्रयास किया है कि कहां-कहां तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सकता है, कहां-कहां तकनीकों के इस्तेमाल से सरकार के लीकेजों (Leakages) को रोका जा सकता है, जनता को अधिकाधिक सुविधाएं दी जा सकती है। हमने इसका बहुत गहन अध्ययन किया और मुझे सदन को बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि शासन के सभी विभागों में आई.टी. के उपयोग को बढ़ावा देने एवं इसका सफल अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए **छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेस** की स्थापना की जायेगी। बजट में आई.टी. उपकरण एवं आधुनिक सॉफ्टवेयर इत्यादि की व्यवस्था के लिए **266 करोड़** का प्रावधान किया गया है। इससे शासन के समस्त विभागों में स्शासन एवं पारदर्शित स्निश्चित की जा सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, तकनीकी प्रयोग आधारित रिफॉर्म और सुशासन, ये जो रिफार्म्स होंगे और गवर्नेंस होंगे, यही आने वाले 05 वर्षों में 05 लाख करोड़ के जी.एस.डी.पी. को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने के लिए आवश्यक तीव्र आर्थिक विकास दर का आधार बनेगा। तकनीकी प्रयोगआधारित रिफॉर्म्स और गुड गवर्नेंस के माध्यम से हम अपने जी.एस.डी.पी. को आने वाले 5 साल में दोगुना करके दिखाने की बड़ी चुनौती को स्वीकार किये हैं।

3. तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय (CAPEX) सुनिश्चित करना। (Ensuring maximum capital expenditure amidst all the challenges) :-

किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के उच्च विकास दर के लिए कैपेक्स अर्थात् पूंजीगत व्यय आधारभूत स्तम्भ होता है।

अध्यक्ष महोदय, आर्थिक अध्ययन यह कहता है कि यदि 100 रूपये के पूंजीगत व्यय से जी.डी.पी. में 247 रूपये की वृद्धि होती है। इसलिए किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसके कैपेक्स में अधिकाधिक वृद्धि की जाये। इस बजट में तमाम चुनौतियों के बाद भी हम पूंजीगत व्यय के प्रावधान में गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि करने का काम किया है। (मेजों की थपथपाहट) जबिक औसतन आप देखेंगे कि पिछले 5 सालों में कैपेक्स मे वृद्धि 5 सालों के औसत में 12 प्रतिशत रही है। जबिक इस बजट में 20 प्रतिशत का कैपेक्स वृद्धि की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को लेकर बजट का निर्माण किया गया है।

4. प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल (Optimum utilization of Natural Resources)

अध्यक्ष महोदय, हमारा चौथा पिलर होगा प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल (Optimum utilization of Natural Resources) हमारा छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है । इन संसाधनों का सुनियोजित उपयोग करते हुये उससे होने वाले लाभों का छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना हमारा चौथा पिलर के रूप में इस रणनीति का हिस्सा होगा ।

5. अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नयी संभावनाओं पर जोर (Emphasis on new possibilities of service sector of the economy)

हमारा पांचवा पिलर होगा, अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर । छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य के अनुरूप इको-टूरिज्म सर्किट विकसित करना, 05 शक्ति पीठों को विकसित करके धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, आई.टी.सेक्टर की स्थापना, हेल्थ डेस्टिनेशन के रूप में छत्तीसगढ़ को विकसित करना, वेडिंग डेस्टिनेशन, बिजनेस टूरिज्म, कान्फ्रेंस डेस्टिनेशन, जैसे नये उभरते संभावनाओं का लाभ प्रदेश को मिल सके, इसके लिये रोडमैप तैयार करेंगे । अध्यक्ष महोदय, सेवा क्षेत्र में देश की औसतन जो जी.डी.पी. पर योगदान है, वह करीब 55 प्रतिशत के लगभग है, जबिक हमारे छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान अभी मात्र 31 प्रतिशत है, इसे बढ़ाकर ही हम छत्तीसगढ़ की आर्थिक उननित को सुनिश्चित कर सकते हैं।

6. सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना (Ensuring private investment):-

अध्यक्ष महोदय, हमारा छठवां पिलर होगा सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश को सुनिश्चित करना । हमारे छत्तीसगढ़ में आधुनिक आर्थिक दर्शन के अनुरूप रेड टेपिज्म के स्थान पर रेड कारपेट की निवेश संस्कृति का हम विकास करेंगे । माडर्न इकॉनामी फिलासॉफी जैसे "मिनिमम गवर्नेंस" Eodb इज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, सिंगल विंडो प्रणाली, ऑनलाईन परमिशन, मिनिमम परमिशन जैसी व्यवस्थाओं की स्थापना करके हम आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेंगे । इसी तारतम्य में PPP पब्लिक प्रायवेट पार्टनरिशप के आदर्श प्रयोगों के लिये नीति आयोग, अखिल भारतीय प्रबंधन संस्थान, आईआईएम्स जैसे विशेषज्ञ संस्थाओं का हम सहयोग लेना सुनिश्चित करेंगे । इन सब का सहयोग लेते हुये जो प्रायवेट इन्वेस्टमेंट है, उसको भी बढ़ावा देने का हम करेंगे ।

7. बस्तर सरगुजा की ओर भी देखो (Focus of Bastar-Surguja):-

अध्यक्ष महोदय, हमारी रणनीति का सातवां पिलर होगा, फोकस ऑन बस्तर एण्ड सरगुजा, बस्तर और सरगुजा की ओर भी देखो, यह हमारा आर्थिक रणनीति का सातवां स्तम्भ है। (मेजों की थपथपाहट) पिछले पांच वर्षों में कांग्रेस के कार्यकाल में बस्तर सरगुजा क्षेत्र आर्थिक विकास की दृष्टि से अछूते रहे हैं। इन क्षेत्रों की एअर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिये सार्थक पहल की जायेगी। ईको टूरिज्म डेस्टिनेशन, नेचरोपैथी डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने हेतु प्रयास किये जायेंगे। बस्तर क्षेत्र में लघु वनोपज के प्रस्संकरण हेतु उद्योगों की स्थापना की जायेगी। सरगुजा क्षेत्र में उद्यानिकी, मछलीपालन जैसी संभावनाओं को भी प्रोत्साहित किया जायेगा। इस प्रकार समन्वित प्रयास करते हुये इन क्षेत्रों की आर्थिक संभावनाओं को पूरी तरह से मूर्त रूप प्रदान किया जायेगा। यह हमारी रणनीति का सातवां स्तम्भ होगा।

8. DOP विकेन्द्रीकृत विकास पॉकेट्स (Decentralisation Development Pockets)

हमारी रणनीति का आठवां स्तम्भ होगा, डीडीपी डिसेंट्रलाईज डेवलपमेंट पाकेट्स, विकेन्द्रीयकृत विकास पाकेट्स की स्थापना करने पर हमारा जोर होगा । छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, मध्य मैदानी भाग और दक्षिणी भाग की अपनी अलग-अलग आर्थिक विशिष्टतायें हैं । इन विशिष्टताओं के अन्रूप तीव्र आर्थिक विकास की विकेन्द्रीकृत नीति पर काम करते ह्ये, विकेन्द्रीयकृत विकास पाकेट्स अर्थात डीडीपी की स्थापना को हम सुनिश्चित करेंगे । रायपुर, भिलाई जैसे क्षेत्रों की अपनी अलग विशिष्टता है, इसलिये इसके आसपास के क्षेत्रों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की जायेगी । इस क्षेत्र को विश्व स्तरीय आई.टी. सेक्टर, वेडिंग डेस्टिनेशन, एज्केशन डेस्टिनेशन, हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की हमारी रणनीति होगी। नवा रायप्र अटल नगर में इस बजट में लावलीह्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं दुर्ग में सेंटर ऑफ एंटरप्रिन्योरशिप की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है । (मेजों की थपथपाहट) इससे द्र्ग-भिलाई में आई.टी.सेक्टर को प्रमोट करने का, उसे प्रोत्साहित करने का हमारा क्रांतिकारी प्रयास होगा । स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने के लिये **इन्क्यूबेशन सेंटर** की स्थापना बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आऊट ऑफ सोर्सिंग, केपीओ क्नॉलेज प्रोसेस आऊट ऑफ सोर्सिंग को आकर्षित करने के लिये इन क्षेत्रों में **आई.टी. पार्क** की स्थापना के लिये हम रणनीतिबद्ध और विजनरी ढंग से कार्य करेंगे। नवा रायप्र में आई.टी.आधारित रोजगार सृजन हेत् प्लग एण्ड प्ले मॉडल का विकास किया जायेगा। इससे आर्थिक विकास और रोजगार मृजन के नये अवसर विकसित होंगे । रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़ जैसे प्रमुख नगरों को विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने की एक रणनीतिबद्ध योजना के तहत हम काम

करेंगे । कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों के अनुरूप प्रमुख नगरों को ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने की एक रणनीतिबद्ध योजना के तहत हम काम करेंगे।

कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों के अनुरूप औद्योगीकरण की नीति को आगे बढ़ायेंगे। मैदानी कृषि प्रधान जिलों में कृषि आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिये भी विशेष फोकस किया जायेगा।

9. छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास :-

अध्यक्ष महोदय, हमारी रणनीति का नवा स्तंभ है, छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास। हमर छत्तीसगढ़ राज्य हर 1956 ले सन् 2000 तक शोषण के शिकार रिहीस। ये 44 साल के बीच म लगभग 04 दशक तक कांग्रेस के एकछत्र राज रिहीस। लेकिन कांग्रेस हर छत्तीसगढ़ ल नवा राज्य नइ बनाईस। छत्तीसगढ़ के नवा राज्य के रूप में कोन्हु स्थापना करिस, त ओर हर हमर भाजपा के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हर करिस। (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ी बोली ल राजभाखा बनाय के बुता ल भी अगर कोई करिस तो भाजपा के सरकार हर हि करिस। अउ अवया बेरा म छत्तीसगढ़ के बानी-भाखा, तिज-तिहार, परम्परा-संस्कृति, साहित्य, सब ल आगु बढ़ाय के बुता ल भी करे के हमर संकल्प है। छत्तीसगढ़ के प्रति हमर सरकार के जो भावना हे, ओला मुंगेली जिला के रहैया श्री केदार परिहार जी हर कविता के रूप में बड़ा अच्छा तरीका से व्यक्त करे हे, मे हर बताना चाहत हों :-

"मरके देवलोक झन जातेंव, कान्हु जनम झन पातेंव। छत्तीसगढ़ ल छांव करे बर, मैं छानही बन जातेंव।।" (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, किव की कल्पना है और यही हमारी सरकार की कल्पना है। हमारी सोच है कि मरने के बाद हमको कोई देवलोक नहीं चाहिए, मरने के बाद हमको कोई पुनर्जन्म नहीं चाहिए। हम छत्तीसगढ़ को छांव करने के लिये छानही बनना चाहते हैं। यही हमारी सरकार की भावना है। (मेर्ज़ों की थपथपाहट)

10. क्रियान्वयन का महत्व (Importance of Implementation) :-

अध्यक्ष महोदय, हमारी रणनीति का 10वां स्तंभ होगा क्रियान्वयन का महत्व। Importance of Implementation.

अध्यक्ष महोदय, हितोपदेश में एक श्लोक है :-

"उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै:।

न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा:।।" (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, शेर कितना भी बलशाली हो, उसके मुख पर मृग आकर खुद प्रवेश नहीं कर जाती है। अगर उसे मृग का शिकार करना है तो उद्यम करना पड़ता है, बिना उद्यम के कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। मन में खयाली पुलाव मात्र से कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ क्रियान्वयन हमारी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

पिछली सरकार ने "गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" का खयाली पुलाव परोसा और उसका नतीजा निकला. "बोरबो छत्तीसगढ़"। हम "गढ़बो" से पहले "करबो" पर ध्यान केंद्रित करेंगे, यही हमारा संकल्प है। (मेजों की थपथपाहट)

मोदी जी ने चुनाव में "बदलबो-बदलबो" का नारा दिया था। वह हमारे लिये चुनावी और राजनीतिक स्लोगन मात्र नहीं है। यह उस समय के अष्ट तंत्र को बदलने के लिये था। यह नारा आज भी हमारी सरकार आने के बाद भी उतना ही प्रासंगिक है, जो छत्तीसगढ़ की आर्थिक और सामाजिकम व्यवस्था को बदलने के लिये है। यह "बदलबो-बदलबो" के नारा का अभिप्राय हमारे लिये बहुत दूर तक है। अब यह स्लोगन छत्तीसगढ़ के 03 करोड़ लोगों के उद्यम से विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में बदलने के लिये हैं। यह "बदलबो-बदलबो" नारा का, मोदी जी के इस नारा का बहुत गहरे मायने हैं।

अध्यक्ष महोदय, इन 10 आधार स्तंभों को फोकस में रखते हुये हम आर्थिक विकास की गित को आगे बढ़ाने के लिए सतत कार्य करेंगे। इस प्रक्रिया में हमें अनेक विशेषज्ञ संस्थाओं के परामर्श की लगातार आवश्यकता होगी। देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिस को हमारी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप लागू करने की हम पहल करेंगे। इस पूरे नॉलेज प्रोसेसिंग की, ब्रेन स्टॉर्मिंग की प्रक्रिया को एक संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के लिये हम **छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद (Chhattisgarh Economic Advisory Council)** का गठन किया जायेगा। यह विष्णुदेव साय जी की सरकार ने निर्णय लिया है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बहुत सुस्पष्ट है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी रगों में है। हमारी रग-रग में है। इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना को व्यक्त करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि :-

"भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है।
ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की भूमि है।
ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है।
इसकी नदी-नदी, हमारे लिए गंगा है,
इसका कंकर-कंकर, हमारे लिए शंकर है।
हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए,
और मरने के बाद भी गंगाजल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई
कान लगाकर स्नेगा, तो एक ही आवाज आएगी-

भारत माता की जय !!" (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की समर्पण की लाईनें हैं।

हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सबसे बड़े प्रतीक पुरूष मर्यादा पुरूषोत्तम श्री राम हैं। उनके द्वारा स्थापित रामराज की अवधारणा से बड़ा सुशासन का कोई दूसरा उदाहरण दुनिया में नहीं मिल सकता। रामचरित मानस में रामराज की व्याख्या करते हुए गोस्वामी तुलसी दास जी ने लिखा है कि :-

रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसी दास जी ने राम राज्य को परिभाषित करते हुए कहा है:"दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, रामराज्य काहू निहं व्यापा" अर्थात् शासन का ऐसा मॉडल जो जनता के शारीरिक, मानसिक और भौतिक, तीनों के एकीकृत विकास में सहायक हो।

सभी प्रकार के कष्टों को दूर किया जा सके। यह रामराज्य की उदाप्त कल्पना है। इसी प्रकार की परिकल्पना हमको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत में 'मानव एकात्मवाद' में भी दिखती है। जब वे कहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 'एकात्म मानव दर्शन' भी शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चित्त के इसी एकीकृत विकास पर ध्यान केन्द्रित करने की बात कहता है।

रामराज्य की अवधारणा को आदर्श मानकर हम लगातार कार्य करेंगे। Good Gavarnence, Reforms सारी चीजों को Implement करने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ हमारी सरकार समर्पित होकर कार्य करेगी।

प्रशासनिक आदर्श के रामराज की इसी ऊंचाई को पाने की दिशा में हमारी सरकार भी निरंतर प्रयास करती रहेगी।

आर्थिक स्थिति

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ :-

वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर दर पर वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 6.56 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है जबिक इसी अविध में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

वर्ष 2023-24 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 3.23 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र में 7.1 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 5.02 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

प्रचलित दर पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 में 04 लाख 64 हजार 398 करोड़ अनुमानित था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 05 लाख 05 हजार 886 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार प्रचलित दर पर जी.एस.डी.पी. में पिछले वर्ष की तुलना में 8.93 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2023-24 में जी.एस.डी.पी. में कृषि क्षेत्र का योगदान 15.32 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 53.50 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र का योगदान 31.19 प्रतिशत अनुमानित हैं।

वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 01 लाख 47 हजार 361 रूपये संभावित है, जो गत वर्ष की तुलना में 7.31 प्रतिशत अधिक है।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के उपरोक्त आंकड़े, विशेष तौर पर स्थिर दरों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 6.56 प्रतिशत की वृद्धि होना अर्थव्यवस्था की धीमी गति का सूचक है।

वर्ष 2023-24 का जी.एस.डी.पी. का जो 6.56 प्रतिशत का ग्रोथ रेट है, यह राष्ट्रीय औसत 7.32 प्रतिशत से भी कम है, जो अर्थव्यवस्था की धीमी गति को स्पष्ट रूप से बता रहा है।

वर्ष 2030 तक 10 लाख करोड़ के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजीगत निवेश में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी। साथ ही कृषि क्षेत्र के अलावा विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र सिहत सभी सेक्टर्स में पारदर्शिता के साथ युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता होगी।

क्योंकि हमारे सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र में हमारा योगदान अभी भी 31 प्रतिशत है जबिक राष्ट्रीय औसत लगभग 55 प्रतिशत के बराबर है हमको इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

"छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी'

अध्यक्ष महोदय, इस बजट के विभागवार प्रावधानों की जानकारी देने के पहले **मोदी जी की** गारंटी को पूर्ण करने के लिए हमारी सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों का विवरण सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी के इस बजट में प्रावधान किये गये हैं, मैं जिनका जिक्र करना चाहता हूँ।

कैबिनेट की पहली बैठक में ही हमने **प्रधानमंत्री आवास योजना** के लंबित 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने का निर्णय लिया है। (मेजों की थपथपाहट)

इसके लिए द्वितिय अनुपूरक बजट में 3800 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था और 2024-25 में भी **8 हजार 369 करोड़** का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

मोदी की दूसरी गारंटी **महतारी वंदन योजना** की स्वीकृति दी जा चुकी है। 01 मार्च 2024 से योजना के तहत पात्र महिलाओं को 12 हजार रूपये वार्षिक का भुगतान किया जायेगा। (मेजों की थपथपाहट) हम मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं।

25 दिसम्बर 2023 को **सुशासन दिवस** के अवसर पर 12 लाख से अधिक किसानों को **03 हजार 716 करोड़** रूपये के लंबित **धान बोनस** की राशि भ्गतान की जा च्की है। किसानों के लिए कृषक

उन्नित योजना लागू करने के लिए बजट में 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

मोदी की गारंटी का अगला बिन्दु हर घर निर्मल जल अभियान को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन योजना में 04 हजार 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) इस राशि से ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का पानी उपलब्ध कराया जायेगा।

इससे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का बजट पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना बढ़ गया है। ग्रामीण विकास विभाग के बजट में भी बड़ी वृद्धि हुई है।

तेंद्पत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 05 हजार 500 की दर से संग्रहण शुल्क भुगतान करने का कैबिनेट से अनुमोदन दिया जा चुका है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने संकल्प लिया था कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को 10 हजार रुपये प्रति वर्ष की दर से उन्हें सहायता करेंगे।

भूमिहीन खेतिहार मजदूरों को **10 हजार रुपये** की वार्षिक सहायता देने के लिए **दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना** वर्ष 2024-25 से लागू की जायेगी। इसके लिए बजट में **500 करोड़ रुपये** का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

पी.एस.सी. परीक्षा के घोटाले की जांच का कार्य सी.बी.आई. को सौंपने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। भविष्य में पूर्ण पारदर्शिता के साथ पी.एस.सी. परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा और आवश्यक रिफार्म पी.एस.सी. में सुनिश्चित किये जायेंगे। यह संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। (मेजों की थपथपाहट)

युवाओं के लिए **छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना** वर्ष 2024-25 इसी वित्तीय वर्ष से चालू करने का प्रावधान किया गया है। इसी बजट में प्रावधान किया गया है।

स्टेट केपिटल रिजन के विकास की योजना तैयार करने के लिए भी 05 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इनवेस्ट इंडिया की तर्ज पर **इनवेस्ट छत्तीसगढ़** आयोजित करने के लिए भी **05 करो**ड़ का प्रावधान किया गया है।

मोदी की गारंटी के तहत **शक्तिपीठ परियोजना** का डी.पी.आर. एवं निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए **05 करोड़ रुपये** का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और श्री राम लला के प्रति प्रदेश की जनता की अपार आस्था को देखते हुए हमारी सरकार ने श्री राम लला दर्शन योजना मोदी की गारंटी के तहत चालू की है।

प्रदेश वासियों को श्री राल लला के दर्शन करवाने हेतु 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

कृषि एवं सहायक गतिविधियों में आय वृद्धि

अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र के क्छ महत्वपूर्ण प्रावधानों का मैं जिक्र करना चाह्ंगा।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में किसानों एवं भूमिहीन कृषि मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कृषि एवं सहायक गतिविधियों (उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन) के प्रोत्साहन हेतु समन्वित प्रयास किया जायेगा।

कृषि विभाग के बजट में विगत वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए कुल 13 हजार 438 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।(मेजों की थपथपाहट)

कृषि उन्नति योजना के क्रियान्वयन के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।

किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 2003 से पहले 15 प्रतिशत, 16 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण मिलता था, जिसे पिछली भा.ज.पा. की सरकार ने शून्य प्रतिशत तक लाया था। इसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए 08 हजार 500 करोड़ की साख सीमा निर्धारित की गई है। इस राशि पर ब्याज अनुदान के लिए 317 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इस बजट में जो प्रावधान हैं, वह मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा।

सिलिफिली जिला सूरजपुर एवं रायगढ़ में शासकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, कुनकुरी जिला जशपुर में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रामचंद्रपुर जिला बलरामपुर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी महाविद्यालय तथा खड़गवां जिला मनेन्द्रगढ़-चिरिमरी-भरतप्र में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी। (मेजों की थपथपाहट)

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत ग्राम सतरेंगा में पर्यटन विकास की दृष्टि से एक्वा पार्क की स्थापना की जायेगी। इस हेत् 05 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

कृषि में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की स्थापना एवं राज्य स्तरीय नवीन कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है।

द्रग एवं सरग्जा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना की जायेगी।

रासायनिक उर्वरकों की जांच के लिए सरगुजा जिले में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी।

उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए 14 विकासखण्डों में नवीन नर्सरी की स्थापना की जायेगी एवं पूर्व से संचालित 20 नर्सरियों में अतिरिक्त पद मृजित किये जायेंगे। पशु औषधालय कुंवारपुर एव माड़ीसरई जिला जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं पशु औषधालय कोल्हेनझरिया जिला जशप्र का पशु चिकित्सालय में उन्नयन का प्रावधान किया गया है।

ग्राम भोरिंग जिला महासमुंद, ग्राम चरोदा जिला-सक्ती, ग्राम किरगी जिला राजनांदगांव, ग्राम खैरवना जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा ग्राम मटासी जिला जशपुर में नवीन हेचरी की स्थापना करके मत्स्य पालन को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके लिए 01 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

<u>सिंचाई</u>

सिंचाई रकबे के विस्तार के लिए नवीन सिंचाई परियोजनाओं हेतु 300 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। संभावित सिंचाई परियोजनाओं की सूची में 10 करोड़ रूपये से अधिक लागत के 156 कार्य प्रस्तावित किए गए हैं।

लघु सिंचाई की चालू परियोजनाओं हेतु 692 करोड़ रूपये, नाबार्ड पोषित सिंचाई परियोजनाओं के लिए 433 करोड़ रूपये तथा एनीकट एवं स्टॉपडेम निर्माण हेतु 262 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

केलो सिंचाई परियोजना की नहरों का काम रायगढ़ जिले में वर्षों से अधूरा था। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहर निर्माण के काम को पूरा किया जायेगा। इसके लिए 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन हेतु डिजिटल सूचना प्रणाली विकसित की जायेगी। इसके लिए राज्य जल सूचना केन्द्र की स्थापना हेतु 01 करोड़ 56 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग में यह टेक्नोलॉजी का उपयोग है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, बांधों में पानी बहता रहता है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए सिंचाई बांधों की देखभाल एवं मरम्मत के लिए राज्य बांध सुरक्षा संगठन का पृथक से सेटअप स्वीकृत किया गया है। सिंचाई बांधों की सुरक्षा के लिए इस बजट में 72 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इससे सिंचाई बांधों की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाना संभव हो सकेगा।

सहकारिता

सहकारिता की क्षेत्र में सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सहकारी सिमितियों की लाभप्रदता एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। 100 प्राथमिक कृषि साख सहकारी सिमितियों में खाद्य एवं बीज भंडारण हेतु गोदाम निर्माण के लिए 26 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक द्वारा विशेष प्रकार के आवश्यक प्रशिक्षण संचालित किए जा सके, इसके लिए प्रशिक्षण संस्थान का भवन निर्माण किया जाएगा और उसके लिए इस बजट में 05 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

अध्यक्ष महोदय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गत वर्ष के बजट प्रावधान में 70 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इस वर्ष के बजट में 17 हजार 529 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत जो आवास निर्माण करने हैं, उसके लिए इसी बजट में 08 हजार 369 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 02 हजार 788 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नवीन सड़कों के निर्माण एवं वर्तमान सड़कों के संधारण हेतु 841 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार की गतिविधियों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 561 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों एवं कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत 19 जिलों में पी.वी.टी.जी. बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सड़क एवं पुल निर्माण हेत् 300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 12 वृहद पुलों एवं सड़कों के लिए 94 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

म्ख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 50 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों का विकास

विशेष रूप से कमजोर समूह के विद्यार्थियों हेतु कबीरधाम, गरियाबंद, कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा, धमतरी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जशपुर एवं नारायणपुर में संचालित आवासीय विद्यालयों के लिए 13 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

भवनविहीन छात्रावास/आश्रमों के 46 भवन निर्माण हेतु 78 करोड़ 10 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बलरामपुर महाराजगंज, शंकरगढ़, डिण्डो, राजपुर, लखनपुर, कांसाबेल, बगीचा, दोकड़ा, बतौली, मनोरा, कोतबा, दुलदुला, पण्डरीपानी, तपकरा तथा नर्मदापुर तथा पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास जशपुर नगर के भवन निर्माण हेत् प्रावधान किया गया है।

प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास पैक्, दोकड़ा, रौनी, गाला, कोतबा, बागबाहरा, लोदाम, दुलदुला, लवाकेरा, पण्डरीपानी, कांसाबेल, बटईकेला, कुनकुरी, देवगढ़, मंगारी, बतौली, घाटवर्रा, नवापारा लखनपुर, कमलेश्वरपुर तथा लुण्ड्रा प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास करजी, धौरपुर, बोदा, अंबिकापुर के भवन निर्माण हेत् प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

पोस्ट मैट्रिक अनुस्चित जाति बालक छात्रावास महासमुंद, प्री. मैट्रिक अनुस्चित जाति बालक छात्रावास बाजार अतिरया, कोरबा, करतला एवं प्री. मैट्रिक अनुस्चित जाति कन्या छात्रावास अंबिकापुर के भवन निर्माण हेत् प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत जिला रायगढ़ में नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना हेत् इस बजट में 75 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

जिला मुख्यालय बलरामपुर में 100 सीटर आदिवासी क्रीड़ा परिसर की स्थापना एवं भवन निर्माण हेत् **03 करोड़ 10 लाख** रूपये का प्रावधान किया गया है ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को यू.पी.एस.सी. की परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिये द्वारिका में एक यूथ हॉस्टल हमारी पिछली सरकार के द्वारा बनाया गया था । अभी 65 बच्चों को सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति देकर तैयारी करायी जाती है । इन 65 बच्चों के सीटों को सीधा 3 गुना के लगभग वृद्धि करते हुए 200 बच्चों के लिये यू.पी.एस.सी. की तैयारी कराने का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) इन अतिरिक्त सीट्स पर प्रवेशित विद्यार्थियों को विभाग द्वारा निर्धारित दर पर शिक्षण श्लक सह आवास भत्ता का भृगतान किया जायेगा । इस हेत् 04 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

पोषण एवं खाद्य सुरक्षा

अध्यक्ष महोदय, पोषण एवं खाद्य सुरक्षा अंतर्गत प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत् देश भर के 80 करोड़ हितग्राहियों के लिये नि:शुल्क चावल वितरण की अविध में 05 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है । राज्य शासन द्वारा भी मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के हितग्राहियों को आगामी 05 वर्ष तक नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है । (मेजों की थपथपाहट) इस बजट में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत 03 हजार 400 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण से बचाव हेतु फोर्टिफाइड राइस के वितरण के लिये 209 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

शक्कर वितरण योजना अंतर्गत 150 करोड़ रूपये, गुड वितरण हेतु 81 करोड़, अन्त्योदय अन्न योजना अंतर्गत चना प्रदान करने हेतु 400 करोड़ एवं रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु 139 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

उपभोक्ता कल्याण अंशदान (कार्पस) फण्ड योजना अंतर्गत 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

पेयजल की व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय, पेयजल की व्यवस्था के संबंध में प्रदेशवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत गत् वर्ष के बजट को लगभग दुगुना बढ़ाते हुए **05 हजार 47 करोड़** रूपये का प्रावधान इस वर्ष किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

मोदी जी की जल जीवन मिशन योजना में 12 लाख 54 हजार 692 ग्रामीण परिवारों को नल-जल कनेक्शन देने के लिए राज्यांश मद में **04 हजार 500 करोड़** का प्रावधान किया गया है।

जल जीवन मिशन की मॉनिटरिंग के लिये डैशबोर्ड एवं राज्य पोर्टल का निर्माण किया जायेगा । यहां भी टेक्नालॉजी का उपयोग करके हम व्यवस्था को दुरूस्त करने का प्रयास कर रहे हैं । शिकायत निवारण एवं नये कनेक्शन हेतु ऑनलाईन आवेदन की व्यवस्था शुरू की जायेगी । जल की गुणवत्ता की ऑनलाईन मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जायेगी ।

वाड्रफनगर जल आवर्धन योजना हेत् 01 करोड़ 82 लाख का प्रावधान किया गया है ।

ग्रामों में पेयजल प्रदाय हेतु 71 करोड़ एवं नलकूपों के अनुरक्षण हेतु 110 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के लिये 26 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

मात् शक्ति एवं नौनिहालों का विकास

महतारी वंदन योजना अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को 12 हजार रूपये वार्षिक डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया जायेगा । इससे महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी ।

सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र एवं पूरक पोषण आहार हेतु 700 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। पूर्व से संचालित समान उद्देश्य वाली योजनाओं को समायोजित करते हुए, इस स्कीम की जो बहुत सारी Multiplicity थी उसके कारण 10 नवीन अम्ब्रेला योजना प्रारंभ की जायेगी । इसके लिये 628 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिये 117 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

ग्राम पंचायतों में महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिये **महिला सदन** बनाने की एक नवीन योजना हमारी सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी है। (मेजों की थपथपाहट) इसके लिये **50 करोड़** रूपये का इस बजट में प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

खेल एवं युवा कल्याण

पारम्परिक खेलों को पुर्नजीवित करने के लिये **छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना** प्रारंभ की जायेगी । इस हेत् **20 करोड़** रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

जशपुर जिले के कुनकुरी में **मॉडर्न खेल स्टेडियम** का निर्माण किया जायेगा । इस हेतु **02 करोड़** रूपये का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

जिला रायगढ़ एवं बलौदाबाजार में **इंडोर स्टेडियम काम्प्लेक्स** का निर्माण किया जायेगा । इस हेत् **04 करोड़** रूपये का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश के जो 05 नवीन जिले गठित हुए हैं । इन्हें पिछली सरकार ने गठित किया है । वहां जिला कार्यालयों की स्थापना हेतु **250 लाख** रूपये का प्रावधान खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत किया गया है ।

कला, साहित्य, खेल एवं समाज सेवा के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष **छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान** दिया जायेगा। इस मद में **01 करोड़ 50 लाख रूपये** का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

भू-राजस्व व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

अध्यक्ष महोदय, रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग जिले में राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, रायपुर तहसील ऐसे तहसील हैं, जहां बस्तर संभाग के सभी जिलों में जितने राजस्व प्रकरण नहीं हैं, उससे ज्यादा एक-एक तहसील पर हैं, इसलिए वहां पर अतिरिक्त पद सृजित करके राजस्व व्यवस्था को दुरूस्त किया जायेगा। इस हेतु तहसीलदार के 30 और नायक तहसीलदार के 15 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

भू-नक्शों का जियो-रिफ्रेन्सिंग कराया जायेगा तथा प्रत्येक भू-खंड में यू.एल.पिन नंबर देते हुए भू-आधार कार्ड जारी किया जायेगा। नगरीय क्षेत्रों में 1 : 500 के स्केल पर भूमि का नवीन सर्वेक्षण प्रारंभ किया जायेगा। इससे शहरी क्षेत्रों में छोटे भू-खण्डों को भू-नक्शे पर दर्ज किया जाना संभव हो सकेगा।

भू-अभिलेखों को सिविल न्यायालयों से लिंक किया जायेगा। इससे सिविल न्यायालय द्वारा भूमि संबंधी प्रकरणों में पारित आदेशों के परिपालन में भू-अभिलेख का सुधार कार्य ऑनलाइन प्रक्रिया से संभव हो सकेगा।

भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया को ऑनलाइन एवं सरल किया जायेगा।

कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

राज्य में कानून-व्यवस्था की मजबूती के लिए राज्य पुलिस बल में 01 हजार 889 पदों की वृद्धि की गई है। (मेजों की थपथपाहट)

नक्सल ऑपरेशन में जाने वाले राज्य पुलिस बल के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त रेडी-टू-ईट फूड की व्यवस्था हेत् बजट में प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों की सुरक्षा की दृष्टि से स्पाईक रजिस्टेन्ट बूट देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) साइबर क्राइम के प्रकरणों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए कबीरधाम, कोरबा, राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले में 04 नवीन साइबर पुलिस थानों की स्थापना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

सीमावर्ती जिलों से मानव तस्करी के प्रकरणों में पीड़ित बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए राजनांदगांव, कबीरधाम, रायगढ़, जगदलपुर एवं जशपुर जिले में 05 नवीन महिला थाना की स्थापना का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

डायल-112 की सुविधाओं का पूरे प्रदेश में विस्तार किया जा रहा है। इस कार्य के लिए **149** करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के अंतर्गत 03 जिलों हेतु वाटर टेण्डर, फोम टेण्डर एवं वाटर बाऊजर क्रय किये जायेंगे। इसके लिए **14 करोड़ 70 लाख रूपये** का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

जेल में रहने वाले बंदियों को उनके परिजनों से बातचीज करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 08 जिला जेल एवं 08 उप जेलों में प्रिजन कॉलिंग सिस्टम लगाये जायेंगे। इसके लिए 01 करोड़ 16 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

जेलों की व्यवस्था से संबंधित विभिन्न कार्य जैसे- बंदी बैरक, सी.सी. रोड, आवासीय भवन एवं बाउंड्रीवॉल निर्माण हेत् 32 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए शासकीय आवास निर्माण हेतु, जो कर्मचारी रहते हैं, उन्हें थाना क्षेत्र में ही रहने को मिल सकें, दूर-दराज के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वे रह सकें, इसके लिए 129 करोड़ रूपये एवं पुलिस चौकी, थाना एवं अन्य भवनों के निर्माण हेतु 71 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

न्याय व्यवस्था का सुद्दीकरण

राज्य के दूरस्थ एवं अंतिम छोर पर स्थित जिला बीजापुर में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की जायेगी। (मेजों की थपथपाहट) इस हेतु 44 पदों का सृजन एवं 01 करोड़ 45 लाख रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

40 व्यवहार न्यायालयों तथा 10 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना हेतु 360 पदों का सृजन एवं **21 करोड़** रूपये का प्रावधान किया गया है। जिला मुंगेली में **फास्ट ट्रैक कोर्ट** की स्थापना के लिए 09 पदों का सृजन एवं **33 लाख रूपये** प्रावधान किया गया है।

कटघोरा जिला कोरबा में **परिवार न्यायालय** की स्थापना के लिए 19 पदों का सृजन किया गया है एवं **50 लाख रूपये** का प्रावधान किया गया है।

महासमुंद एवं जगदलपुर में परिवार न्यायालय भवन तथा 24 स्थानों पर व्यवहार न्यायालय, इस प्रकार कुल 26 न्यायालय भवनों का निर्माण किया जायेगा। इस हेतु 30 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 289 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए कुल 21 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

उच्च न्यायालय भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग व्यवस्था एवं वीडियो वाल की स्थापना तथा जेल एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लाइव स्ट्रीमिंग एवं रिकॉर्डिंग हेतु अतिरिक्त सेट-अप एवं कम्प्यूटर उपकरणों की व्यवस्था के लिए 15 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई विभाग नहीं है, जहां टेक्नालॉजी के लिए हमने बजट न दिया हो।

ई-कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु हार्डवेयर इंजीनियर एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के **596** पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां हमने टेक्नालॉजी के लिए बजट न दिया हो । ई-कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु हार्डवेयर इंजीनियर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के 596 पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है ।

नगरीय स्विधाओं का विकास

नगरीय क्षेत्रों में सबके लिए आवास, हाऊसिंग फॉर ऑल योजना अंतर्गत 1002 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। (मेजो की थपथपाहट)

शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अमृत मिशन योजना अंतर्गत 795 करोड़ एवं अधोसंरचना विकास मद अंतर्गत 700 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

रायप्र एवं बिलासप्र स्मार्ट सिटी के लिए 404 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 206 करोड़ एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेंट के लिए 166 करोड़ तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 30 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

नगरीय क्षेत्र में स्थित स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए **300 करोड़** रूपए का प्रावधान किया गया है।

नगर पंचायत कुनकुरी, प्रतापपुर, लोरमी एवं मनेन्द्रगढ़ में **ड्रेनेज सिस्टम** एवं **सीवरेज ट्रीटमेंट** प्लांट की स्थापना के लिए 07 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश के 168 नगरीय निकायों में **ई-गवर्नेंस** के तहत् **बजट एण्ड एकाउंटिंग मॉडयूल** स्थापित करने के लिए 47 नगरीय निकायों में **प्रॉपर्टी सर्वे** किए जाने हेतु जी.आई.एस. आधारित सॉफ्टवेयर निर्माण करने के लिए भी बजट प्रावधान किये गये हैं । इससे प्रॉपर्टी टैक्स की प्राप्तियों में पारदर्शिता आएगी । इन कार्यों के लिए **30 करोड़** रूपए का प्रावधान किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, नगरीय निकायों में रायपुर में एक नालंदा परिसर बना है । राष्ट्रीय स्तर की एक ऐसी लायब्रेरी जिसमें 3000 से अधिक युवा आज वेटिंग में हैं । नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थानों पर सेंट्रल लायब्रेरी-सह-रीडिंग जोन की स्थापना की जाएगी (मेजो की थपथपाहट) और इसके लिए 148 करोड़ रूपए का बजटीय प्रावधान किया गया है ।

शहरों में जल की शुद्धता की ऑटोमेटेड जांच एवं प्रदर्शन प्रारंभ किया जाएगा। रतनपुर और डोंगरगढ़ में पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए **ड्रिंक फ्रॉम टेप** वाटर का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है (मेजो की थपथपाहट)।

छोटे घरों के लिए 15 दिवस के अंतर कम्प्यूटराइज्ड जांच प्रणाली के माध्यम से भवन निर्माण की अनुमति की व्यवस्था लागू की जाएगी (मेजो की थपथपाहट)

आवास एवं पर्यावरण

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा अंतर्गत ई-बस क्रय एवं संचालन हेतु 103 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रीन एनर्जी की दिशा में हमारा एक बड़ा कदम होगा ।

स्टेट कैपिटल रिजन के एकीकृत विकास योजना तैयार करने के लिए 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

आई.टी.इनेबल्ड सेवाओं के अनुकूल अधोसंरचना विकसित की जाएगी । इसके लिए भी **5 करोड़** रूपए का प्रावधान किया गया है ।

नवा रायपुर अटल नगर में केन्द्रीय, मेडिकल हब एवं आंतरिक मार्गों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 30 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

सिटी डेव्हलपमेंट एवं इन्वेस्टमेंट प्रमोशन हेतु 10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन के लिए 206 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है ।

पर्यटन एवं संस्कृति

आम नागरिकों के लिए राज्य में पर्यटन सुविधा बढ़ाए जाने हेतु **मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना** प्रारंभ की जाएगी । इस हेतु **01 करोड़ 50 लाख** का प्रावधान किया गया है ।

शक्ति पीठ परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के पांच शक्तिपीठों अर्थात् रतनपुर, चंद्रपुर, दंतेवाड़ा, कुदरगढ़ एवं डोंगरगढ़ इन पांचों स्थानों को विकसित करने के लिए योजना तैयार की जाएगी । इस हेतु 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है ।

विभागवार महत्वपूर्ण **अभिलेखों को डिजिटल** स्वरूप देने के लिए छत्तीसगढ़ वेब अभिलेखागार में जन-सामान्य को सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा । इस हेतु **03 करोड़** रूपए का प्रावधान किया गया है ।

हमारे वनवासियों की भाषा, आदिवासी भाईयों की भाषा गोंडी भाषा है । गोंडी भाषा के विकास हेतु हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा से गोंडी भाषा में अनुवाद करने वाले सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा, जिससे गोंडी भाषा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस हेतु 2 करोड़, 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में गोंडी, हल्बी जैसी आदि भाषाएं हैं । इन आदि भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ आदि भाषा परिषद् का भी गठन किया जाएगा (मेजो की थपथपाहट) ।

वन एवं जलवायु परिवर्तन

तेंद्र्पत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 4 हजार रूपए से बढ़ाते हुए 05 हजार 500 की दर से संग्रहण का भ्गतान किया जाएगा (मेजो की थपथपाहट) वन क्षेत्रों में इको-ट्रिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई नीति जारी की जायेगी। वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किसान वृक्ष मित्र योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके अंतर्गत निजी भू-स्वामी एवं शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं को वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए सहायता अनुदान अनुदान दिया जायेगा। इस हेतु 60 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

प्रदेश के वनों के सरंक्षण एवं संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कैम्पा योजना में 01 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप वनों के प्राकृतिक पुनरूत्पादन हेतु 240 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

तेन्दुपत्ता संग्राहक परिवार के सदस्य को चरण पादुका वितरित करने हेतु 35 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

लेमरू हाथी रिजर्व परियोजना अंतर्गत फलदार प्रजातियों का वृक्षारोपण, चारागाह विकास, जल की उपलब्धता तथा हाथी-मानव द्वंद के कुशल प्रबंधन के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन और अन्य कार्यों हेत् 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

बारनवापारा अभ्यारण में पर्यटन सुविधाओं के विकास हेतु **01 करोड़** रूपये का प्रावधान किया गया है।

विभाग के कार्यों का वेब एवं मोबाईल बेस्ड प्लेटफार्म तैयार किये जाने के उद्देश्य से प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत 14 करोड़ 77 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

वन विभाग द्वारा किये जाने वाले लकड़ियों की नीलामी के लिए ऑनलाईन ऑक्शन पोर्टल का उपयोग स्निश्चित किया जायेगा।

शिक्षित प्रदेश-विकसित प्रदेश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को तत्परता से लागू किया जायेगा। चरणबद्ध रूप से इसका क्रियान्वयन करते हुए प्रदेश के बच्चों एवं युवाओं को उनकी विशिष्ट योग्यता के अनुरूप विकास के अवसर प्रदान किये जायेंगे। (मेजों की थपथपाहट) डिजिटल एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इको सिस्टम के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

ृशिक्षकों की भर्ती एवं पदस्थापना के लिए पोर्टल आधारित पारदर्शी विश्वसनीय एवं सुगम व्यवस्था लागू की जायेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च, इनोवेशन, गुणवत्ता उन्नयन आदि कार्यों के लिए **छत्तीसगढ़ हायर एज्केशन मिशन** का गठन किया जायेगा।

राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से **छत्तीसगढ़ प्रौदयोगिकी संस्थानों** की स्थापना की जायेगी।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में स्टार्ट-अप, इनोवेशन एवं रिसर्च, को बढ़ावा देने के लिए सेन्ट्रल इंस्ट्र्मेंटेशन फेसिलिटी का उन्नयन किया जायेगा। इस हेतु 02 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर में 20 नवीन शिक्षण विभाग में 33 नवीन स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रांरभ किये जायेंगे। इस हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जायेगी।

आपराधिक न्यायिक तंत्र में निष्पक्ष परीक्षण एवं जांच के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही फोरेंसिक साईंस विषय हेतु अध्ययन शाला प्रारंभ किये जायेंगे। इस हेतु भी बजटीय प्रावधान किये गये हैं। (मेजों की थपथपाहट)

भवन विहीन 20 शासकीय महाविद्यालयों के नवीन भवन निर्माण हेतु 20 करोड़ तथा अन्य निर्माण कार्यों के लिए 10 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।

15 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के नवीन विषय एवं संकाय खोले जाएंगे।

22 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर के नवीन विषय प्रांरभ किये जायेंगे।

सूरजपुर, गरियाबंद, कोण्डागांव, सुकमा एवं बलरामपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाईट की स्थापना की जायेगी।

भवन विहीन 57 शासकीय हाईस्कूलों एवं 39 शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवनों का निर्माण किया जायेगा। इसके लिए बजट में **100 करोड़** रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

नवा रायपुर, अटल नगर में संगीत महाविद्यालय एवं ग्राम बेन्द्री विकासखंड अभनपुर जिला रायपुर में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किया जायेगा। इस हेतु भी बजटीय प्रावधान किया गया है।

नवा रायपुर, अटल नगर में **लाईवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस** की स्थापना की जायेगी। इसके लिए **01 करोड़** का प्रावधान किया गया है।

पिपरिया जिला कबीरधाम में **नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान** की स्थापना की जायेगी। इसके लिए **01 करोड़** रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

विद्यार्थियों एवं आम जनता में विज्ञान के प्रति रूचि उत्पन्न करने एवं विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को समझने के उद्देश्य से राजधानी में साईंस सिटी की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 34 करोड़ 90 लाख का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

खगोल विज्ञान की लोकप्रियता को जन मानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूरजपुर जिले में **एस्ट्रो पार्क** की स्थापना की जाएगी। इसके लिए **2 करोड़ रूपये** का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

प्रदेश के बी.पी.एल. परिवारों को 5 लाख रूपये तक एवं ए.पी.एल. परिवारों को 50 हजार रूपये तक नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए आयुष्मान काई जारी किये जाएंगे। इसके लिए **आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना** के साथ शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना संचालित की जाएगी। इसके लिए 1 हजार, 526 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में 1 हजार, 821 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर का छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्रदेश का प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज है। इसका भवन जर्जर होकर बरसों से चला आ रहा है। **छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान,** बिलासपुर के नवनिर्माण के लिए **700 करोड़ रूपये** की लागत से नवीन भवन का निर्माण किया जाएगा। (मेजों की थपथपाहट)

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर का 1,200 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया जाएगा एवं इसके लिए **776 करोड़ रूपये** की लागत से 700 बिस्तर अस्पताल का भवन निर्माण किया जाएगा।

अंबिकापुर में **सुपर स्पेशितटी हॉस्पिटल** की स्थापना की जाकर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के साथ संयोजित करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर वहां चिकित्सा सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके लिए **50 करोड़ रूपये** का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

राज्य के अस्पतालों को गुणवत्ता उन्नयन की दृष्टि से राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (N.Q.A.S.) सर्टिफिकेशन कराया जाएगा। इस हेतु 12 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

रायगढ़, कवर्धा, गरियाबंद, मुंगेली, बैकुंठपुर, जशपुर एवं नारायणपुर के जिला चिकित्सालयों को आदर्श जिला चिकित्सालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर की स्थापना हेतु 2 करोड़ 70 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

नवीन 5 जिले खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी, सारंगढ़-बिलाईगढ़, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही एवं सक्ती में **सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक** एवं **मुख्य चिकित्सा** एवं **स्वास्थ्य अधिकारी** कार्यालयों की स्थापना की जाएगी। मनेन्द्रगढ़ तथा कुनकुरी में **220 बिस्तर अस्पताल** की स्थापना की जाएगी। बस्तर में नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ क्वार्टर हेतु भी इस बजट में **1 करोड़ रूपये** का प्रावधान किया गया है।

डी.के.एस. सुपर स्पेशितटी हॉस्पिटल, रायपुर एवं फिजियोथेरिपी महाविद्यालय, रायपुर में छात्रावास के निर्माण हेत् 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

300 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 25 जिला चिकित्सालयों एवं 48 क्रियाशील फर्स्ट रिफरल यूनिट के लिए लैब टेक्निशियन के 373 पदों का प्रावधान इस बजट में किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खड़गवा जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उन्नयन के लिए 37 पदों का प्रावधान किया गया है।

उप स्वास्थ्य केन्द्र गोलावण्ड जिला कोण्डागांव को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन हेतु 12 पदों का प्रावधान किया गया है।

सिविल अस्पताल कुरूद जिला धमतरी को 50 बिस्तर अस्पताल से 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया जायेगा।

15 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 276 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है।

शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों में फिजियोथेरेपी, मानसिक स्वास्थ्य एवं नशा मुक्ति तथा योग संबंधी परामर्श सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजनांतर्गत 3 करोड़, 50 लाख रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

मनेन्द्रगढ़, सूरजप्र, बलरामप्र एवं कोण्डागांव में जिला आयुर्वेद कार्यालय प्रारंभ किये जाएंगे।

6 आयुर्वेद औषधालय रतनपुर जिला कोरिया, सेमरिया जिला रायपुर, निकुम जिला दुर्ग, चित्रकोट जिला बस्तर, सुपेबेझ जिला गरियाबंद तथा रेरूमाखुर्द जिला रायगढ़ में खोले जाएंगे।

जिला आयुर्वेद कार्यालय सूरजपुर में 10 बिस्तर के **पॉली क्लिनिक** की स्थापना की जाएगी।

भूमिहीन कृषि मजद्रों, श्रमिकों, निराशितों एवं दिव्यांगों की सहायता

भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता हेतु दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना प्रारंभ की जाएगी।

भूमिहीन कृषि मजदूरों, श्रमिकों, निराश्रितों एवं दिव्यांगों की सहायता

भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता हेतु दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, इसके लिए इस बजट में 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

असंगठित श्रमिकों, असंगठित सफाई कर्मकारों, ठेका मजदूरों, घरेलू कामकाजी महिलाओं एवं हमालों के कल्याण हेतु **अटल श्रम सशक्तिकरण योजना** प्रारंभ की जाएगी, इसके लिए **123 करोड़** का बजटीय प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

विभाग द्वारा असंगठित श्रमिकों के पंजीयन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के ऑन लाईन मानीटिरिंग हेतु श्रमेव जयते पोर्टल आरंभ किया जाएगा। पोर्टल के विकास हेतु 2 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

निराश्रितों, वृद्धजनों, दिव्यांगों, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन योजनाओं का लाभ देने के लिए **01 हजार 400 करोड़ रूपए** का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) इससे लगभग 23 लाख हितग्राहियों को सामाजिक स्रक्षा पेंशन का लाभ मिल पाएगा ।

प्रदेश के दिव्यांगों पर सामाजिक समावेश सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दिव्यांग अनुकूल बनाया जाएगा । इस हेतु सुगम्य छत्तीसगढ़ अभियान में 01 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

वाणिज्य एवं उद्योग

वर्तमान उद्योग नीति की समीक्षा करके नई उद्योग नीति जारी की जाएगी। इसमें राज्य में उपलब्ध, कृषि उत्पाद, वनोपज एवं खनिज संपदा तथा रोजगार मूलक उद्योगों की स्थापना का ध्यान रखा जाएगा और नए उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ कोर सेक्टर में पूर्व से कार्यरत् उद्योगों को क्षमता विकास के लिए भी अन्कूल अवसर प्रदान किए जाएंगे।

प्रदेश में आर्थिक और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त कोरबा-बिलासपुर इंडिस्ट्रियल कारीडोर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट के क्षेत्रों में उपलब्ध उपयुक्त शासकीय भूमि पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा । इस योजना के निर्माण हेत् 5 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है ।

नये औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु 60 करोड़, फूड पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़, लागत पूंजी अनुदान हेतु 200 करोड़ एवं ब्याज अनुदान हेतु 50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए मोदी जी की गारंटी के तहत **छत्तीसगढ़ उद्यम** क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी ।

इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन आयोजित किया जाएगा । इस हेतु 05 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है ।

प्रदेश में अत्याधुनिक **छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप हब** और **नॉलेज प्रोसेस, आऊट सोर्सिंग इकाईयां** स्थापित करने एवं राज्य में एक समृद्ध नवाचार परिस्थितिकीय तंत्र तैयार किये जाने हेतु स्टार्ट अप सिमट का आयोजन किया जाएगा । इस हेत् इस बजट में 01 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

जिला कोरबा में **एल्युमिनियम पार्क** की स्थापना किये जाने हेतु **5 करोड़** रूपए का बजटीय प्रावधान किया गया है ।

प्रदेश के हैण्डलूम, हस्तिशिल्प एवं अन्य स्थानीय उत्पादों की बिक्री एवं प्रचार-प्रसार के लिए मार्केट प्लेस उपलब्ध कराने हेतु राजधानी में राष्ट्रीय स्तर पर जो यूनिटी मॉल का कान्सेप्ट है, उसी तरह का राजधानी रायपुर में **यूनिटी मॉल** स्थापित किया जाएगा, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इसकी लागत लगभग 200 करोड़ रूपए होगी । इसके लिए **80 करोड़** रूपए का प्रावधान इस बजट में होगा । 50 प्रतिशत केन्द्र से मिलेगा ।

<u>ऊर्जा विभाग</u>

5 एच.पी. तक के कृषि पपों को वार्षिक 07 हजार 500 यूनिट तक नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 03 हजार 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इस योजना में 06 लाख 96 हजार कृषि पम्पों को लाभ मिल रहा है ।

हाफ बिजली बिल योजना अंतर्गत 43 लाख 34 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट की खपत तक हाफ बिजली बिल योजना का लाभ प्रदाय किया जा रहा है। जिसके लिए 01 हजार 274 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

कृषि पम्पों के ऊर्जीकरण हेत् 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

कृषकों को सिंचाई की सुविधा हेतु सोलर सिंचाई पम्पों की स्थापना हेतु **670 करोड़** का प्रावधान किया गया है ।

बी.पी.एल. उपभोक्ता को प्रति माह 30 यूनिट की खपत पर निःशुल्क बिजली प्रदान की जाती है । इस हेतु एकल बत्ती कनेक्शन योजना हेतु अनुदान मद में 540 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

सौर सामुदायिक सिंचाई योजना अंतर्गत 795 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करने के उद्देश्य से 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

आई.टी. अधोसंरचना एवं आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेस

प्रशासनिक कार्यों में तेजी, शासकीय धन के कपटपूर्ण संव्यवहार पर रोक तथा प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए आई.टी. अधोसंरचना का तेजी से विकास किया जायेगा । राजधानी मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक प्रशासनिक कार्यों में आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेस को बढ़ावा देने के लिए सभी विभागों में मिलाकर कुल **266 करोड़** का प्रावधान किया गया है। यह हमारी रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

आई.टी. अधोसरंचना एवं आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेस

प्रशासनिक कार्यों में तेजी, शासकीय धन के कपटपूर्ण संव्यवहार पर रोक तथा प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए आई.टी. अधोसरंचना का तेजी से विकास किया जायेगा। राजधानी मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक प्रशासनिक कार्यों में आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेस को बढ़ावा देने के लिए सभी विभागों में मिलाकर कुल 266 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह हमारी रणनीति का एक महतवपूर्ण स्तम्भ है। इन टेक्नालॉजी एक्सपेरीमेंट को सही ढंग से संचालित करने के लिए छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेस की स्थापना का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। तािक टेक्नालॉजी सम्बन्धी चीजों को अच्छे ढंग से लागू किया जा सके।

राज्य शासन द्वारा संचालित सभी प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की एकजाई मॉनिटरिंग अटल डैशबोर्ड के माध्यम से की जायेगी। इसके लिए 05 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

शासकीय धन के आय-व्यय की दैनिक निगरानी के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS-2.0) प्रारंभ की जायेगी।

भारत नेट परियोजना के तहत राज्य की 9,804 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाईबर केबल से जोड़ा जा चुका है। इसके रख-रखाव एवं संचालन के लिए 66 करोड़ की पूल निधि के गठन का प्रावधान किया गया है।

एकीकृत ई.प्रोक्योरमेंट परियोजना के नवीन संस्करण हेतु 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में वाई-फाई के माध्यम से हॉट-स्पॉट स्थापित कर प्रदेश भर में इंटरनेट की पहुंच बढ़ाई जायेगी। इस हेतु प्रथम चरण में 1,000 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई की सुविधा के लिए पी.एम.वाणी परियोजना अन्तर्गत 37 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

शासन के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग किए जा रहे ई-परिसम्पत्ति, मोबाईल एप एवं वेबसाईट की सायबर सुरक्षा हेतु आवश्यक जांच एवं सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की जायेगी।

अधोसरंचना निर्माण

प्रदेश में अधोसरंचना विकास एवं पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए लोक निर्माण विभाग के लिए 08 हजार 17 करोड़ के प्रावधान सहित कुल 22 हजार 300 करोड़ का पूंजीगत मद में प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान गत वर्ष के पूंजीगत प्रावधान से 20 प्रतिशत अधिक है। जबिक पिछले पांच सालों में on an average कैपेक्स में 12 प्रतिशत की ही वृद्धि हो रही थी।

राज्य मार्गों के निर्माण हेतु 190 करोड़, मुख्य जिला सड़कों के निर्माण हेतु 390 करोड़, ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 747 करोड़, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु अतिरिक्त 200 करोड़, शहरी क्षेत्र के मार्ग हेतु 50 करोड़, वृहद एवं मध्यम पुलों के निर्माण हेतु 244 करोड़ तथा रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण हेत् 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 01 हजार 690 नवीन निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इसमें से 01 हजार 268 सड़क कार्य हेतु 737 करोड़, 349 वृहद एवं मध्यम पुल निर्माण हेतु 175 करोड़ तथा 55 भवनों के निर्माण हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

जगदलपुर, बिलासपुर एवं अम्बिकापुर एयरपोर्ट हेतु सुरक्षा उपकरण क्रय किये जाने हेतु 30 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

जशपुर हवाई पट्टी एवं बलरामपुर हवाई पट्टी का उन्नयन एवं सुधार हेतु 16 करोड़ 20 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

रेल लाईनों के लिए भी इस बजट में बड़ा प्रावधान किया गया है। जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं जिला कोरिया अन्तर्गत शहरों के विकास और स्थायित्व के लिए रेल्वे की महत्वपूर्ण परियोजना चिरमिरी-नागपुर हाल्ट की नई रेल लाईन हेतु राशि 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है।(मेजों की थपथपाहट)

कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल लाईन निर्माण तीव्र गति से किये जाने हेतु राशि 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

कर प्रणाली का सुद्दीकरण

कर प्रशासन में मजबूती एवं पारदर्शिता लाने के लिए सभी विभागों में आई.टी.टूल्स की सहायता ली जायेगी । कर प्राप्तियों में स्धार हेत् निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया जायेगा ।

राज्य की राजस्व प्राप्तियों का प्रमुख स्त्रोत वस्तु एवं सेवाकर है । वस्तु एवं सवाकर के संकलन में सुधार एवं पारदर्शिता के लिए राज्य मुख्यालय में **बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट** की स्थापना की जायेगी । इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी (AI) एवं मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए data driven fraud analysis सिहत राजस्व संवर्धन के अन्य उपाय सुनिश्चित किये जायेंगे । इस हेतु बजट में **9 करोड़ 50 लाख** का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) संबंधी अपीलीय मामलों के त्वरित निराकरण हेतु अधिकरण की स्थापना के लिये 05 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

आबकारी करावंचन के प्रकरणों पर नियंत्रण हेतु प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ की जायेगी। इसके लिये विभागीय पदों में वृद्धि, निरीक्षण हेतु वाहन व्यवस्था एवं मॉनिटरिंग हेतु कंप्यूटर उपकरण इत्यादि के लिये 03 करोड़ 88 लाख रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

भूमि एवं भवनों का हस्तान्तरण तथा अन्य विविध पंजीकृत संव्यवहार हेतु राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (NGDRS) सॉफ्टवेयर का उपयोग सभी जिलों में लागू किया जायेगा । इससे धोखाधड़ी एवं बेनामी लेन-देन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा । विचाराधीन संपत्तियों का आटोवेल्यूवेशन मॉड्यूल के तहत बाजार मूल्य की ऑनलाईन गणना का विकल्प होने से राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होगी । इसके लिये 10 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

वर्ष 2024-2025 का बजट अनुमान

अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-2025 का बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ ।

वर्ष 2024-2025 में 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ रूपये की कुल प्राप्ति का अनुमान है, जो कि गत वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों से 22 प्रतिशत अधिक है। (मेजों की थपथपाहट) पिछले पांच वर्षों में बजट के साईज का जो औसत ग्रोथ था, वह 8 प्रतिशत था, जबिक पिछले बजट की तुलना में इस बजट में हम 22 प्रतिशत की वृद्धि बजट के आकार में कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) कर प्राप्तियों में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 68 हजार 400 करोड़, केन्द्र से प्राप्तियां 57 हजार 500 करोड़ एवं पूंजीगत प्राप्तियां 21 हजार 600 करोड़ रूपये अनुमानित है।

वर्ष 2024-2025 के लिये विनियोग का आकार **1 लाख 60 हजार 568 करोड़** का है, सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुर्नप्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ अनुमानित है । राजस्व व्यय 1 लाख 24 हजार 840 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 22 हजार 300 करोड़ रूपये का होगा ।

वर्ष 2023-2024 में पूंजीगत व्यय प्रावधान 18 हजार 660 करोड़ था । वर्ष 2024-2025 में 22 हजार 300 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है ।

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिये, आदिवासी उपयोजना मद में 33 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना मद में 13 प्रतिशत राशि का विशेष प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2024-2025 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिये 45 प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्र के लिये 35 प्रतिशत एवं सामान्य सेवा के क्षेत्र के लिये 20 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

राजकोषीय स्थिति

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा राजस्व संग्रहण के लिये आधुनिक तकनीकों का उपयोग तथा प्रशासन को सरल एवं पारदर्शी बनाने के उपाय किये जा रहे हैं । इससे बिना कोई नया कर अधिरोपित किये राज्य के स्वयं के राजस्व में 22 प्रतिशत की वृद्धि का हमने बड़ा लक्ष्य रखा है । (मेजों की थपथपाहट)

17 दिसम्बर 2018 की स्थिति में राज्य का कुल ऋण भार 41 हजार 695 करोड़ रूपया था, जो विगत 5 वर्षों के दौरान लगभग 91,520 करोड़ रूपये हो गये । इस प्रकार राज्य निर्माण के पश्चात् 18 वर्षों में लिये गये ऋण से भी अधिक ऋण पिछली सरकार द्वारा केवल 5 वर्ष के दौरान लिया गया । जनवरी 2024 की स्थिति में राज्य का कुल ऋण भार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के जी.डी.पी. की तुलना में 18 प्रतिशत है ।

वर्ष 2024-2025 में राज्य का सकल वित्तीय घाटा 19,696 करोड़ रूपया अनुमानित है । जिसमें केन्द्र से पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता ऋण 3 हजार 400 करोड़ रूपया शामिल है । भारत सरकार के निर्देश अनुसार यह राज्य के वित्तीय घाटे का भाग नहीं है । अतः इसे कम करने पर राज्य का शुद्ध वित्तीय घाटा 16,292 करोड़ रूपये होगा । जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 2.90 प्रतिशत है । इस प्रकार एफ.आर.बी.एम. एक्ट में निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर है ।

राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 1 लाख 25 हजार 900 करोड़ रूपया है एवं कुल राजस्व व्यय 1 लाख 24 हजार 824 करोड़ रूपये है । अत: वर्ष 2024-2025 में राजस्व आधिक्य **1 हजार 60 करोड़** रूपये का होगा अर्थात यह बजट (Revenue Surplus) राजस्व आधिक्य वाला बजट है ।

कर प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 के लिये कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है, (मेजों की थपथपाहट) न ही करों की दर में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है। (मेजों की थपथपाहट)

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुआई में भारत आज विश्वगुरू की भूमिका में पुन: आ गया है। आज हम विश्व की 05वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। केवल 10 सालों में 11वें स्थान से आगे बढ़ते हुए हमने 05वें स्थान तक की छलांग लगाई है। कभी बीच में सांप-सपेरों के देश की दुर्भाग्यजनक पहचान बना दिये गए भारत को आज विश्व महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। (मेजों की थपथपाहट) अमृतकाल में अगले 05 सालों के भीतर ही मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हम न केवल इस विकास के भागीदार हैं, बल्कि इस विकास में हमारा बढ़-चढ़कर योगदान भी अपेक्षित है। भले ही हमने अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन यह समय रूकने का नहीं है। मोदी जी के शब्दों में कहूं तो यही समय है, सही

समय है, जब हम कमर कसकर मां भारती और छत्तीसगढ़ महतारी को उसके पुरा वैभव की पुनर्स्थापना हेतु चल रहे महायज्ञ में भागीदार बनें। भले ही हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ प्राप्त करना शेष है। यह समय रूक जाने का नहीं है, बल्कि देश की प्रगति के लिए चलते रहने का है। देश के तेजी से विकसित हो रहे राज्यों के साथ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ को तेजी से आगे बढ़ाने का है। हमारी सरकार के फिलॉसफी को, हमारी सरकार की सोच को, हमारी सरकार के दर्शन को, मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से प्रकट करना चाहता हूं।

गहन-सघन मनमोहक वन तरू, मुझको आज बुलाते हैं

किन्तु किए जो वादे मैंने, याद मुझे आ जाते हैं।

अभी कहां आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है

अभी तो मुझको, मीलों मुझको, मीलों मुझको चलना है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सरकार का विजन है। हम काफी चले हैं। इस प्रक्रिया में अनेक लोगों का योगदान रहा है। आगे और द्रुत गित से चलते रहेंगे। आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यह पालनहारी सरकार है, जो छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर पहुंचायेगी, जो 05 लाख करोड़ के जी.डी.पी. को 10 लाख करोड़ जी.डी.पी. तक पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है, जो एक विजन डॉक्यूमेंट 01 नवंबर, 2024 को प्रस्तुत करने जा रही है। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन सन् 2047, जो विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में परिवर्तित करने वाला होगा।

अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में वर्ष 2024-25 का बजट छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा की दिशा में हमारा पहला कदम है। "राम काज कीन्हें बिनु हमें कहां बिश्रामा" की भावनाओं के साथ वर्ष 2024-25 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगें सदन के समक्ष प्रस्तृत करता हूं।

जय हिन्द ! जय छत्तीसगढ़ ! (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- मैं, आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिये दिनांक 12 एवं 13 फरवरी, 2024 की तिथियां नियत करता हूं।

आय-व्ययक पर सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्तावों की सूचना शनिवार, दिनांक 10 फरवरी, 2024 को अपराहन 3.00 बजे तक दी जा सकती है। कटौती प्रस्ताव के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

<u>अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि</u> श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष

अध्यक्ष महोदय :- अध्यक्षीय दीर्घा में विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय जी उपस्थित हैं। सदन की ओर से उनका स्वागत करते हैं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 12 फरवरी, 2024 को 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित।

(अपराहन 02.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 12 फरवरी, 2024 (माघ 23, शक सम्वत् 1945) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा

सचिव

दिनांक: 09 फरवरी, 2024

रायप्र (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ विधान सभा